संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-22 अंक- 336
पृष्ठ 8
गुरुवार
27 अगस्त 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

# शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- कीलोंग घूमने के दौरान जरूर...

विचार- बांग्लादेश मक्का समझौते में शामिल...

खेल- यशस्वी-वैभव सूर्यवंशी पर बरसे...

## 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं करेंगी फ्री सफर

### सीएम योगी बोले-अपराधियों को अब जेल या जहन्नुम में ही जगह

लखनऊ,संवाददाता। यूपी में 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं आज से रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। सीएम योगी ने बुधवार को 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना' की शुरुआत की। उन्होंने बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

सीएम ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेशभर से आईं बुजुर्ग महिलाओं से बात की। इस दौरान उन्नाव से आईं नीता अवस्थी भावुक हो गईं। उन्होंने रोते हुए योगी से कहा, "महाराज जी, हम बहुत खुश हैं। अब परिवार वाले पैसा दें या न दें, हमें मुफ्त में सफर करने को मिलेगा।"

दूसरी महिला लायका खातून ने कहा, "मैं लखनऊ में रहती हूं। गांव गाजीपुर है। अब वहां फ्री में जा सकूंगी। आपको दिल से शुक्रिया।"

सीएम ने कहा– 27, 28 और 29 अगस्त को हर बेटी, हर मां अपने एक साथी के साथ फ्री में रोडवेज की यात्रा कर सकेंगी। इसके बाद बुजुर्ग महिलाओ को आजीवन मुफ्त सफर का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार अक्टूबर–नवंबर में 50 हजार बेटियों को स्कूटी देगी।

सीएम ने महिलाओं को योजना के स्मार्ट कार्ड भी बांटे। उन्हें एक बैग दिया, जिसमें साड़ी और मिठाई थी। सीएम ने महिलाओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। फिर बसों को रवाना करने के बाद वह एक बस में चढ़ गए। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को दूर किया और अपने मोबाइल से सेल्फी ली। इस दौरान सीएम महिलाओं से कहते नजर आए– मोबाइल की तरफ देखिए।

इससे पहले, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए रोडवेज बसों में ळैै और पैनिक बटन भी लगाए गए हैं।

यूपी सरकार 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' पर हर महीने 22.50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत हर दिन करीब 90 हजार से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं सरकारी रोडवेज बसों में मुफ्त सफर करेंगी। सफर के दौरान महिलाओं को अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। भाजपा ने साल 2022 के घोषणापत्र में इस योजना को लागू करने का वादा किया था।

2011 की जनगणना के मुताबिक, यूपी में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। इनमें 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या करीब 1 करोड़ है। न्ैव्ज्ब् के मार्च 2022 से मार्च 2023 के सर्वे के मुताबिक, रोज करीब 18 से 20 लाख यात्री रोडवेज बसों से सफर करते हैं। इनमें 33ः यानी करीब 5.94 लाख महिलाएं शामिल हैं।

राजनीतिक एक्सपर्ट के मुताबिक, इस योजना का असर सिर्फ एक करोड़ महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा,।

## नेपाल बाढ़: बिहार में हाई अलर्ट, अमित शाह ने सीएम सम्राट से की बात

नई दिल्ली,एजेंसी। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को संभावित संकट से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को तैनात किया जा रहा है। बिहार CMO का कहना है है कि एक हाई–लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल से बिहार में बाढ़ का पानी आने की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलों में खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी तटबंधों की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी लगातार निगरानी की जानी चाहिए। बांधों और तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें रात में गश्त पर खास जोर दिया गया है। जोखिम वाले और प्रभावित इलाकों में लाउडस्पीकर या माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके लोगों तक जरूरी जानकारी और चेतावनी लगातार पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश के किसी भी राज्य की अधिकारियों ने बताया है कि गंडक नदी के किनारे बसे जिलों में बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। पूर्वानुमान में नेपाल के गंडक जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा, लमजुंग और तनहुँ जिलों के साथ–साथ कोसी जलग्रहण क्षेत्र के दोलखा और सिंधुपालचोक जिलों में भी अचानक बाढ़ का ज़्यादा खतरा होने की चेतावनी दी गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक हाई–लेवल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रभावित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

### भारत ने नस्लीय भेदभाव को लेकर यूएन की रिपोर्ट की खारिज, कहा

## ये राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन कमेटी ( यूएन सीईआरडी) की देश के बारे में की गई टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इसे राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने 11–12 अगस्त को जिनेवा में आई सीईआरडी के तहत भारत की 11वीं सामायिक समीक्षा के बाद नस्लीय भेदभाव उन्मूलन कमेटी के बयान पर गौर किया।

### अगस्त माह का सावित्री देवी स्मृति सम्मान शहर समता महिला काव्यगोष्ठी शिलांग इकाई की सदस्या मल्लिका डे विष्णु को दिया जाएगा

प्रयागराज। हर माह मिलने वाला सावित्री देवी स्मृति सम्मान अगस्त 2026 का शहर समता महिला काव्यगोष्ठी शिलांग इकाई से आदरणीया मल्लिका डे विष्णु जी को दिया जाएगा। रचनाकार मल्लिका डे विष्णु जी पर चार पेज का सावित्री देवी स्मृति सम्मान विशेषांक भी प्रकाशित होगा, जिसमें रचनाकार को 30–35 कविताएं, कहानी, अपना जीवनवृत्त और अपना आत्मसंघर्ष टाइप करके देना पड़ेगा। साथ में एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो भी।

### प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह से की बात,कहा-

## हर संभव मदद का भरोसा

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (26 अगस्त) को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और पड़ोसी देश में विनाशकारी बाढ़ से हुई जान–माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने शाह को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया और संकट से निपटने में नेपाल की मदद के लिए हर संभव मानवीय और राहत सहायता की पेशकश की। एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जान–माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों पर निकटता से समन्वय कर रही हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत पड़ोसी देश में विनाशकारी बाढ़ के बाद जल्द से जल्द नेपाल को राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है।

बुधवार को मध्य नेपाल में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और नदी के किनारे बसे इलाकों में भारी तबाही हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से कम से कम एक दर्जन पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुँचा है। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ाय बताया जा रहा है कि यह पानी तिब्बत की तरफ से आया था। इस आपदा से तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धाडिंग जिलों के साथ–साथ काठमांडू के दक्षिण–पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला भी प्रभावित हुआ। नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी से रसुवा जिले के तिमुरे और पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान हुआ।

## कर्नाटक में वंदेमातरम के 2 पैरे ही गाए जाएंगे : शिवकुमार

### हम पार्टी के फैसले के साथ, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है

बेंगलुरु ,एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद (पैरे) ही गाए जाएंगे। मैं पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हूं और हम इस फैसले पर कायम रहेंगे। भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। शिवकुमार बेंगलुरु में इंडिया टुडे के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने कहा– स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम उनकी जानकारी के बिना गाया गया था, लेकिन भविष्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अब राष्ट्रगीत के दो ही छंद गाए जाएंगे। दरअसल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी ॅब ने 19 अगस्त को ऐलान किया था कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती दो पैरा ही गाएगी। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गान को लेकर हुए विवाद के बाद आया। भाजपा ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया था। गृह मंत्री अमित शाह– कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से दो–राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ।

### दिल्ली लक्ष्मी योजना : रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिला उपहार12

## सीएम रेखा ने सौंपा 2500 का लाभार्थी पत्र

नई दिल्ली ,एजेंसी। दिल्ली की महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा घोषित दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिलने का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम मेंआयोजित विशेष कार्यक्रम में करीब 2,500 लाभार्थी महिलाओं को आधिकारिक लाभार्थी पत्र सौंपे। तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल किया गया और 65 महिलाओं को मंच पर बुलाकर पत्र दिया गया। बाकी महिलाओं को भी 1 सितंबर से पहले तक पत्र मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर कहा, शदिल्ली के लिए यह बात हमने पहले दिन ही कह दी थी कि दिल्ली की बहनों को 2,500 रुपए देना हमारा संकल्प है, तो आज

दिल्ली लक्ष्मी योजना को वास्तविक रूप से जनता तक पहुंचाने वाले इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूं।

1 अगस्त को हमने इस योजना को शुरू किया और सिर्फ 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 2,500 की योजना की पहली ढाई हजार लाभार्थियों को हमने अप्रूवल लेटर भेज दिया है और 1 सितंबर को उनके खातों में अगस्त महीने का पैसा पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी तय तारीख को इस योजना का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। यह लगातार चलने वाली योजना है। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, मोदी की एक–एक गारंटी पूरी कर रही हैं, दिल्ली की करीब 9 लाख महिलाओं ने इस योजना पर यकीन किया और फॉर्म भरा है, अब उनको लाभ देना शुरू किया जा रहा है। पहले होली पर सिलेंडर दिया, अब दिवाली पर आएगा, पिंक कार्ड से मुफ्त बस के साथ सफर सुगम किया है। दिल्ली में 9वीं पास करने वाली सभी बेटियों को साइकिल देने का काम शुरू किया है, अगले साल भी जो बच्चियां 9वीं में जाएंगी, उनको भी साइकिल दी जाएंगी। अब हर घर को बिजली का मीटर लगेंगे, करीब 2.5 लाख घरों में मीटर लगेगा।

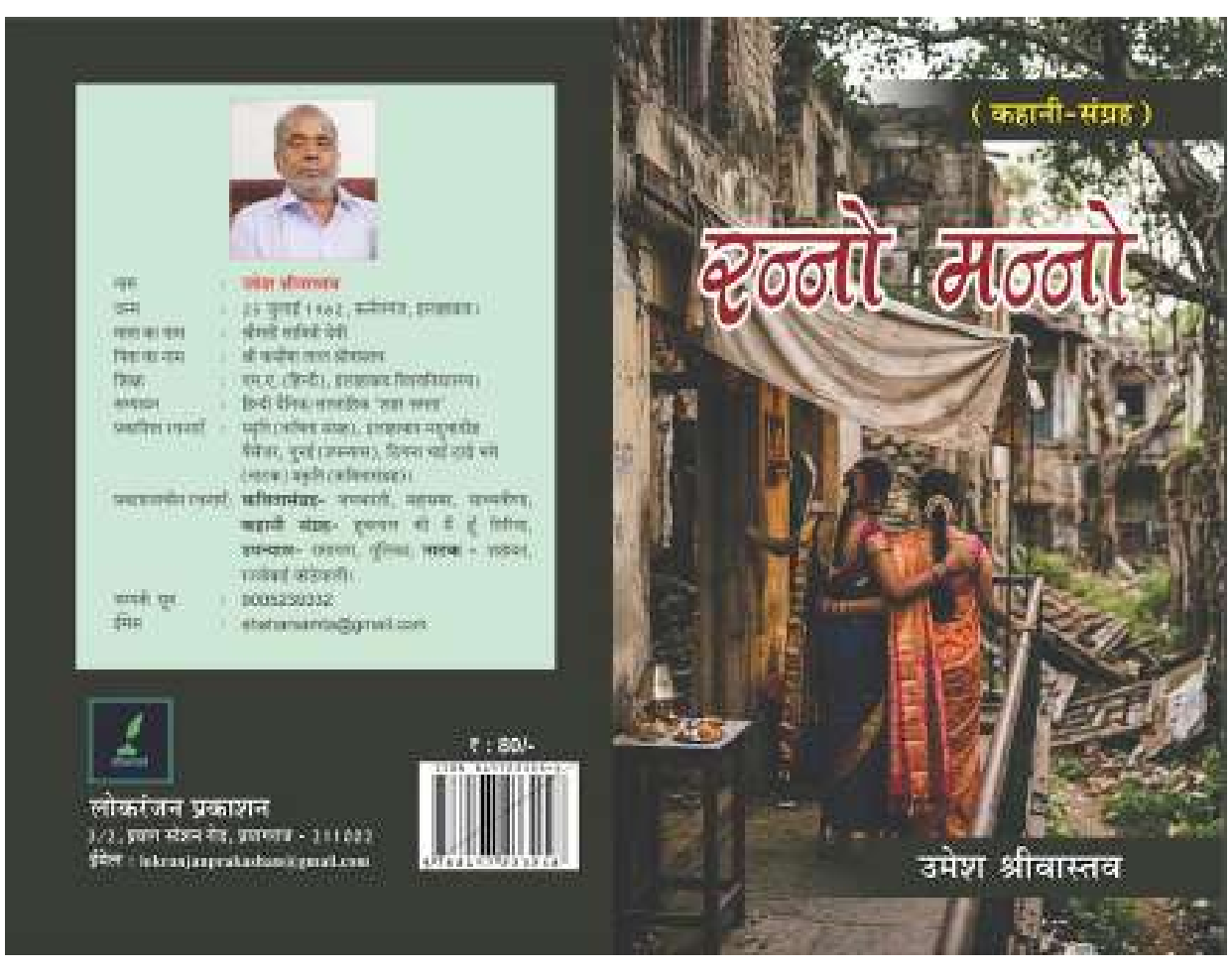

## हाईकोर्ट: घायलों के बयानों में मामूली विरोधाभास से अविश्वसनीय नहीं होती पूरी गवाही, उम्रकैद की सजा बरकरार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पुराने हत्याकांड में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कहा, हत्या जैसे जघन्य मामलों में घायल गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभास से पूरी गवाही अविश्वसनीय नहीं माना जा सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पुराने हत्याकांड में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कहा, हत्या जैसे जघन्य मामलों में घायल गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभास से पूरी गवाही अविश्वसनीय नहीं माना जा सकती है। यह फैसला न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने असगर व अन्य की अपील पर सुनाया है। मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में 18 दिसंबर 1985 को हुए हत्याकांड से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने मामन हुसैन, उनके बेटे जाहिद, पत्नी शरीफन पर धारदार हथियार व लाठी से हमला किया था। गंभीर चोटों से मामन हुसैन की 23 दिसंबर 1985 को मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ असगर व उसके साथियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। अपील के दौरान असगर और एक अन्य की मौत हो गई। लिहाजा, कोर्ट ने जीवित बचे जबीर की अपील पर सुनवाई की। जबीर के अधिवक्ता ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास, स्वतंत्र गवाहों की गैरहाजिरी और हत्या के कारण साबित नहीं होने को आधार बनाया। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल के दौरान हमले में मरने वाले के घायल बेटे जाहिद और पत्नी शरीफन ने गवाही दी थी। उन्होंने घटना की पुष्टि की थी। कोर्ट ने कहा कि घटना में घायल प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही विश्वसनीय है। मामूली विरोधाभास के आधार पर उनकी पूरी गवाही को दर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें आईं चोटें मेडिकल साक्ष्य से समर्थित हैं। इसलिए किसी अन्य गवाह की गवाही नहीं होने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि जब प्रत्यक्ष साक्ष्य भरोसेमंद हो तो घटना की वजह का कमजोर या साबित न होना निर्णायक नहीं होता। सभी आरोपियों के हथियारों से लैस होकर साथ आने और हमले में सक्रिय भागीदारी से साझा मंशा भी साबित होती है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने से इन्कार कर अपील खारिज कर दी। साथ ही जबीर की सजा बरकरार रखते हुए उसे 20 सितंबर तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

## हाईकोर्ट: स्कूली बच्चों के लिए सड़क निर्माण को वन विभाग जल्द जारी करे एनओसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के चंदूपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चों की परेशानी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वन विभाग को स्कूल तक जाने वाली 1.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के चंदूपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चों की परेशानी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वन विभाग को स्कूल तक जाने वाली 1.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया है। कहा है कि एनओसी सामान्य गति से नहीं, बल्कि शीघ्रता से जारी किया जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने स्वतरू संज्ञान जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 1.81 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन 1.6 किलोमीटर हिस्सा वन भूमि में आने से निर्माण वन विभाग की अनुमति पर निर्भर है। वर्ष 2015 में निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन एनओसी न मिलने से परियोजना बाद में रद्द कर दी गई। अब राज्य सरकार ने नए सिरे से एनओसी हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि अंतरिम व्यवस्था के तहत सड़क को वाहनों के चलने योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश और भूभाग की प्रकृति के कारण अस्थायी व्यवस्था जल्द खराब हो जाती है। राज्य ने सीमेंट की सड़क को आवश्यक बताया।कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और हमीरपुर के संभागीय वन अधिकारी को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। आदेश की प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भेजने को कहा गया।

### नाम संशोधन सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मेखला दवे (MEKHALA DAVE) के जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटिवश मेघला दवे एवं पिता का नाम सनदीप देव अंकित है जो कि गलत है, सही नाम मेखला दवे (MEKHALA DAVE) एवं पिता का नाम संदीप दवे (SANDEEP DAVE) है, वास्तव मे लिखत–पढ़त मे मेखला दवे (MEKHALA DAVE) एवं संदीप दवे (SANDEEP DAVE) को ही सत्य माना जाए जो कि मेरी निजी जानकारी मे सत्य व सही हैं।

(संदीप दवे)
पुत्र राजीव दवे निवासी एन–73, डायमंड डिस्ट्रक्ट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड़, बैंगलोर कर्नाटक।

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती रोमी त्रिपाठी पत्नी श्री अमित पाण्डे यह सूचित करती हूं की शादी के बाद मैंने अपना नाम बदलकर रोमी पाण्डे (ROMI PANDEY) रख लिया है। भविष्य में मुझे रोमी पाण्डे (ROMI PANDEY) नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाय। मेरे सभी सरकारी और सेवा संबंधी दस्तावेजों में मेरा यही नाम मान्य होगा।

**श्रीमती रोमी पाण्डे**
**पत्नी श्री अमित पाण्डे**
**निवासी– 5B/9 भावापुर, जीटीबी नगर करेली, प्रयागराज**

# आठ दिन बाद पुराने प्लेटफार्म पर लौटी विभूति एक्सप्रेस, रामबाग स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन शुरू

प्रयागराज। आठ दिन के लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार फिर पटरी पर लौट आई है। प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 के ट्रैक से जलभराव खत्म होने के बाद आज से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया। खास बात यह रही कि दोपहर में विभूति एक्सप्रेस अपने पुराने प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची और अब यहीं से हावड़ा के लिए रवाना होगी।

प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर पिछले कई दिनों से जलभराव के कारण प्रभावित रेल परिचालन अब सामान्य होने लगा है। प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 के ट्रैक पर भरा पानी निकल जाने के बाद रेलवे ने इन पटरियों पर ट्रेनों का संचालन बुधवार दोपहर बाद से शुरू कर दिया है। दोपहर में विभूति एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर एक पर लाया गया। अब यही ट्रेन यहां से हावड़ा के लिए रवाना की जाएगी।

जलभराव के चलते बीते आठ दिनों से रामबाग स्टेशन के इन प्लेटफार्मों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित था। ट्रैक पर पानी भरने के कारण ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्मों से चलाया जा रहा था और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए थे, जबकि परिचालन व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए रेलवे को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़े थे।

विभूति एक्सप्रेस के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचने के साथ ही रामबाग स्टेशन की पुरानी व्यवस्था बहाल होने का संकेत मिल गया है। करीब आठ दिन बाद ट्रेन अपने निर्धारित पुराने प्लेटफार्म पर लौटी है। दोपहर में ट्रेन को प्लेटफार्म पर लाए जाने के बाद यात्रियों में भी राहत देखने को मिली। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की ओर से जलनिकासी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पानी कम होने के बाद ट्रैक और प्लेटफार्म की स्थिति की जांच की गई और संचालन के लिए उपयुक्त पाए जाने पर ट्रेनों को दोबारा इन पटरियों पर लाने का निर्णय लिया गया।

झूंसी से चल रही थी मेमो ट्रेन

रामबाग स्टेशन पर पानी भरा होने के कारण यहां से बनारस के लिए जाने वाली मेमू ट्रेन एक सप्ताह से झूंसी से चलाई जा रही थी। मेमू का संचालन झूंसी से रामबाग के बीच नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे महकमे ने 26 सितंबर से स्थिति सामान्य होने के संकेत दिए थे।

# देरी माफी की अर्जी लंबित होने पर भी अपीली, अदालत दे सकती है अंतरिम राहत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की अर्जी लंबित होने मात्र से अपीलीय अदालत की अंतरिम संरक्षण देने की शक्ति खत्म नहीं हो जाती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की अर्जी लंबित होने मात्र से अपीलीय अदालत की अंतरिम संरक्षण देने की शक्ति खत्म नहीं हो जाती। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि अंतरिम राहत नहीं मिलने पर प्रस्तावित अपील ही निष्फल हो सकती है तो अदालत विषय–वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए सीमित अवधि का अंतरिम आदेश पारित कर सकती है।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कानपुर नगर निवासी नीलाभ गुप्ता की याचिका पर की। कोर्ट ने कानपुर नगर के अपर जिला न्यायाधीश के 31 मार्च को पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने अपीलीय अदालत को देरी माफी की अर्जी पर जल्द निर्णय लेने और उसके बाद 60 दिन में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया है।

किरायेदारी विवाद से जुड़ा है मामला

मकान मालिक याची ने उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम के तहत किरायेदारों के खिलाफ किरायेदारी के विवाद को लेकर मुकदमा दाखिल किया था। किराया न्यायाधिकरण ने दो सितंबर 2025 को मकान मालिक के पक्ष में आदेश पारित कर किरायेदारों को परिसर से बेदखल करने और बकाया दिलाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ किरायेदारों ने रेंट अपील दाखिल की। अपील के साथ देरी माफी की अर्जी और अंतरिम संरक्षण की मांग भी की गई। अपर जिला न्यायाधीश ने 31 मार्च को किराया न्यायाधिकरण के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटया।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि अपील दाखिल करने में हुई देरी माफी की अर्जी लंबित रहते हुए अपीलीय अदालत को अंतरिम संरक्षण नहीं देना चाहिए था। मकान मालिक ने मध्यस्थता केंद्र की 24 फरवरी 2026 की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो पहले ही खत्म हो चुकी है। हलांकि, कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। स्पष्ट किया कि देरी माफी की अर्जी लंबित होना अपने आप में अपीलीय अदालत को अंतरिम संरक्षण देने से रोकता नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह भी नहीं है कि अदालत देरी माफी के सवाल को तय किए बिना अपील के गुण–दोष पर सुनवाई शुरू कर सकती है।

प्रस्तावित अपील के मुद्दे को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया अंतरिम आदेश और अपील को गुण–दोष के आधार पर सुनना दो अलग–अलग बातें हैं। अंतरिम संरक्षण का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि देरी माफी के सवाल पर फैसला होने तक ऐसी स्थिति न बन जाए, जिससे अपील ही निष्फल हो जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा मामले में अपीलीय अदालत ने अपील के गुण–दोष पर कोई फैसला नहीं किया था।

उसने केवल इसलिए अंतरिम संरक्षण दिया। क्योंकि, जब किराया न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी। संरक्षण नहीं मिलने पर अपील निष्फल हो सकती थी। मध्यस्थता रिपोर्ट पर कोर्ट ने पाया कि वह अपीलीय अदालत में समय पेश नहीं की गई थी। लिहाजा, इसके आधार पर अपीलीय अदालत के अंतरिम आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, ऐसी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पक्ष अपीलीय अदालत के समक्ष उचित राहत मांग सकता है।

# एक सप्ताह से लापता हुए युवक की हत्या कर शव यमुना में फेंका, पूछताछ में खुलासा

प्रयागराज। पुरामुफ्ती से छह दिन पहले लापता युवक मोनू (35) की हत्या करके लाश को यमुना नदी में फेंक दी गई है। यह सनसनीखेज खुलासा गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने की है। पुरामुफ्ती से छह दिन पहले लापता युवक मोनू (35) की हत्या करके लाश को यमुना नदी में फेंक दी गई है। यह सनसनीखेज खुलासा गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने की है। मंगलवार को ग्रामीणों थाने का घेराव किया था। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जब कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया तो आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इसके बाद पुलिस अब उफनाई यमुना में शव की खोजबीन में जुटी है। पूरामुफ्ती से छह दिन पहले लापता युवक मोनू (35) का छह दिन बाद भी सुराग न लगने पर मंगलवार को ग्रामीणों ने थाने घेराव किया था। ग्रामीणों का कहना था कि मोनू का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं लगा है। पुलिस मामले में कोई तेजी नहीं दिखा रही है। थाना प्रभारी ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया था। बुधवार को पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि मोनू की हत्या कर दी गई है और शव को यमुना नदीं में फेंक दिया गया है। महगांव निवासी युवक के मामा कमलेश कुमार के मुताबिक, 19 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे मोनू पूरामुफ्ती थाने के पास मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान कार सवार कुछ लोग उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद से उसका पता नहीं चला। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। परिजनों का कहना है कि 20 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मोनू की तलाश में कार्रवाई नहीं हुई।

## हाईकोर्ट का आदेश: अपील या पुनरीक्षण लंबित होने से आदेश के क्रियान्वयन पर नहीं लग सकती रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल अपील या पुनरीक्षण लंबित होने के आधार पर किसी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए संबंधित अपीलीय या पुनरीक्षण अदालत से अंतरिम राहत प्राप्त करनी होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल अपील या पुनरीक्षण लंबित होने के आधार पर किसी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए संबंधित अपीलीय या पुनरीक्षण अदालत से अंतरिम राहत प्राप्त करनी होगी। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कुशीनगर के बहारन प्रसाद व पांच अन्य की ओर से दाखिल लीव टू अपील की अर्जी और विशेष अपील का निस्तारण करते हुए की। मामला एकल पीठ के राजस्व मामले में पारित आदेश से जुड़ा था। एकल पीठ ने संबंधित एसडीएम को रिट याचिकाओं के समूह में पारित आदेशों को चार सप्ताह में लागू करने का आदेश दिया था। अपीलकर्ताओं का कहना था कि वे मामले में आवश्यक पक्षकार हैं और सीमांकन आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। आदेश वापस लेने की उनकी अर्जी खारिज हो चुकी थी। इसके खिलाफ अपील भी खारिज हुई और पुनरीक्षण लंबित था। कोर्ट ने पाया कि लंबित अपील या पुनरीक्षण में किसी अदालत ने अंतरिम रोक नहीं लगाई है। ऐसे में आदेश के क्रियान्वयन पर रोक का आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर पक्षकार होने के अधिकार पर कोई निष्कर्ष देना लंबित पुनरीक्षण को प्रभावित कर सकता है। लिहाजा, कोर्ट ने दोनों अर्जियों का निस्तारण कर अपीलकर्ताओं को संबंधित अदालत में अंतरिम राहत मांगने की स्वतंत्रता दी है।

## सेंट एंड्रयूज डिग्री कालेज में फर्जी नियुक्ति का प्रयास करने पर एफआईआर दर्ज

प्रयागराज। गोरखपुर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर एस. डोमिनिक राजकुमार ने कैंट थाने में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गोरखपुर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर एस. डोमिनिक राजकुमार ने कैंट थाने में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद फर्जी नियुक्ति पत्र और सर्कुलर तैयार कर दूसरे व्यक्ति को कार्यवाहक प्राचार्य बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की है। एफआईआर के मुताबिक, प्रो. एस. डोमिनिक राजकुमार ने बताया कि कॉलेज का संचालन सेंट एंड्रयूज कॉलेज एसोसिएशन सोसाइटी के माध्यम से होता है। सोसाइटी की नियमावली में प्रबंध समिति को प्राचार्य की नियुक्ति, निलंबन और बर्खास्तगी का अधिकार दिया गया है। इसी प्रबंध समिति को लेकर हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है। शिकायत में कहा गया कि गोरखपुर मंडल सोसाइटीज एवं चिट्स फर्म्स सहायक रजिस्ट्रार ने सात मार्च को पत्र जारी किया था। इसमें हाईकोर्ट का फैसला आने तक प्रबंध समिति की बैठक कर कोई बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

आरोप है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर मोस्ट रेवरेंट परितोष कैनिंग की कथित सह पर बिशप मॉरिस एडगर दान, रेव. रोशन लाल और रैना सैमुअल समेत अन्य लोगों ने मिलकर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए। इसमें रैना निवेदिता सैमुअल को कॉलेज का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त करने की बात कही गई। इसके साथ ही एक कथित सर्कुलर भी तैयार कराया गया। इसमें प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों से इस पर हस्ताक्षर कराए गए। आरोप है कि अशोक नगर स्थित एक साइबर कैफे में इंटरनेट की मदद से कुछ दस्तावेज तैयार किए गए। एसीपी सिविल लाइंस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने फर्जीवाड़ा और जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने समेत अन्य आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरोप पूरी तरह बेबुनियाद रू एडगर दान

बिशप मॉरिस एडगर दान ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर जारी किया गया पत्र पूरी तरह सही है। पत्र पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के भी हस्ताक्षर हैं। मामले की निष्पक्ष और सही तरीके से जांच होने पर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

## स्कूली बच्चों के लिए सड़क निर्माण को वन विभाग जल्द जारी करे एनओसी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के चंदूपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चों की परेशानी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वन विभाग को स्कूल तक जाने वाली 1.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के चंदूपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चों की परेशानी को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वन विभाग को स्कूल तक जाने वाली 1.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का आदेश दिया है। कहा है कि एनओसी सामान्य गति से नहीं, बल्कि शीघ्रता से जारी किया जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने स्वतरू संज्ञान जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 1.81 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन 1.6 किलोमीटर हिस्सा वन भूमि में आने से निर्माण वन विभाग की अनुमति पर निर्भर है। वर्ष 2015 में निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन एनओसी न मिलने से परियोजना बाद में रद्द कर दी गई। अब राज्य सरकार ने नए सिरे से एनओसी हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि अंतरिम व्यवस्था के तहत सड़क को वाहनों के चलने योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश और भूभाग की प्रकृति के कारण अस्थायी व्यवस्था जल्द खराब हो जाती है। राज्य ने सीमेंट की सड़क को आवश्यक बताया।कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और हमीरपुर के संभागीय वन अधिकारी को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। आदेश की प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भेजने को कहा गया, ताकि एनओसी में और देरी न हो। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

## अभिभावक बनने के लिए अयोग्य साबित किए बिना पिता से बेटी की अभिरक्षा नहीं छीन सकते

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी की अभिरक्षा के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता प्राकृतिक अभिभावक है और उसे अयोग्य साबित किए बिना बेटी की कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पिता को चार वर्षीय बच्ची की अभिरक्षा सौंपते हुए नाना पक्ष को मुलाकात का अधिकार भी दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी की अभिरक्षा से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कहा है कि पिता प्राकृतिक अभिभावक है। जब तक उसे नाबालिग का अभिभावक बनने के लिए अयोग्य साबित नहीं किया जाता, तब तक उसे बेटी की अभिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। अभिरक्षा के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बच्चे का कल्याण है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी अभिषेक की अपील पर दिया है। बच्ची का जन्म 2022 में हुआ था। वह नवंबर 2023 तक पिता के साथ रही। इसके बाद मां के साथ मायके चली गई। बच्ची की मां की फरवरी 2024 में बीमारी के दौरान मौत हो गई। पिता ने बेटी की अभिरक्षा के लिए मुकदमा दाखिल किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा कि पिता के खिलाफ लगाए गए दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार बच्ची की मां की मौत एक गंभीर बीमार की वजह से हुई थी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि उनकी बीमारी और मौत कथित सिर की चोट के कारण हुई थी। कोर्ट ने चार वर्षीय बच्ची की अभिरक्षा के लिए पिता की ओर से दायर अपील स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट के 31 मई 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बच्ची की अभिरक्षा उसके पिता को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही बच्ची के नाना पक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज में दोपहर दो से शाम पांच बजे तक मुलाकात का अधिकार दिया है।

## संक्षिप्त

### माल में ईद मिलाद–उन–नबी पर माल में निकला भव्य जुलूस

लखनऊ (संवाददाता)। ईद मिलाद–उन–नबी के अवसर पर बुधवार को राजधानी लखनऊ के माल कस्बे में मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस–ए–मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए जुलूस का जगह–जगह लोगों ने स्वागत किया। जुलूस के दौरान युवाओं और बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। लोग शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस में शामिल हुए। आयोजन के दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। जुलूस को लेकर माल पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। थाना प्रभारी नवाब अहमद के नेतृत्व में पुलिस बल पूरे जुलूस मार्ग पर मुस्तैद रहा। पुलिस की निगरानी में जुलूस निर्धारित मार्ग से शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा और कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। आयोजकों ने लोगों से शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जुलूस के समापन पर देश में अमन–चौन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन पर आयोजकों ने पुलिस–प्रशासन का आभार जताया।

### लखनऊ से बेंगलुरु जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी, एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। धमकी की सूचना विमान के बेंगलुरु पहुंचने से कुछ समय पहले सामने आई, जिसके बाद केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया गया। विमान ने सुबह करीब 9.40 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। जानकारी के मुताबिक, लखनऊ से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6म्231 के एक क्रू सदस्य को विमान के लैंडिंग से पहले धमकी के बारे में पता चला। क्रू सदस्य ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत तुरंत पायलट को इसकी जानकारी दी। इसके बाद एयरपोर्ट पर संबंधित सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई। विमान के सुरक्षित उतरने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के लिए लिया। विमान और उसमें मौजूद सामान की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। शुरुआती जांच में अभी तक विमान के अंदर या सामान में कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। सुरक्षा एजेंसियां धमकी को फिलहाल फर्जी मानकर जांच आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन किसी भी संभावित जोखिम को देखते हुए विमान की विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों की ओर से सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही धमकी के स्रोत और उसकी प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। विमान की तलाशी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत की जा रही है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां विमान, यात्रियों के सामान और अन्य संबंधित हिस्सों की जांच करती हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे की पुष्टि या उसे खारिज किया जा सके। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार फ्लाइट सुरक्षित रूप से बेंगलुरु पहुंच चुकी है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। धमकी किस माध्यम से मिली और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी भी जांच की जा रही है।

### पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में यूपी देश में तीसरे स्थान पर

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है। पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। अब तक 17.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो चुके हैं। लोग पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ई–रिक्शा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन पारंपरिक पेट्रोल–डीजल वाहनों की तुलना में अलग ऊर्जा व्यवस्था पर आधारित होने के कारण जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने में सहायक है। इससे ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक एवं टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा मिल रहा है।डायरेक्टर नेडा रविन्दर सिंह के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग की सुविधा मिल रही है और ईवी अपनाने को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदेश में स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश का पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचना और प्रदेश में 17.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

### गांवों की सड़कें विकास और समृद्धि की नई राह–शिव सहाय

लखनऊ (संवाददाता)। डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमि के तत्वावधान में प्रांतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के 91वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण शिव सहाय अवस्थी ने ग्रामीण विकास में सड़कों की भूमिका तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया।श्री अवस्थी ने उपमुख्यमंत्री एवं ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विस्तार और गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। श्री मौर्य का स्पष्ट विजन है कि प्रदेश का कोई भी गांव बेहतर सड़क संपर्क से वंचित न रहे और सड़क के माध्यम से गांव तक विकास की प्रत्येक सुविधा पहुंचे। उपमुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की प्रत्येक माह समीक्षा करते हैं। श्री मौर्य ने पीएमजीएसवाई की सड़कों में एफडीआर जैसी आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीक के उपयोग पर विशेष बल दिया है।

## शहर समता विचार मंच की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सम्पन्न



प्रयागराज। शहर समता विचार मंच के तत्वावधान में रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता रचना सक्सेना ने की, उमेश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। आशा जाकड़ ने मधुर स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

काव्य गोष्ठी का संयोजन एवं कुशल संचालन उमा मिश्रा 'प्रीति' ने किया। इस अवसर पर साधना खरे, श्रद्धा श्रीवास्तव, सुनीता गुप्ता, सुषमा सिंह 'उर्मि', अनीता दुबे, छाया सक्सेना, संतोष मिश्रा, डॉ. शशि जायसवाल, रेणुका पटेल, पूनम पांडे, डॉ. प्रतिभा दीवान एवं शोभा त्रिपाठी ने रक्षाबंधन की भावनाओं से ओत–प्रोत अपनी सुंदर रचनाओं की भावपूर्ण प्रस्तुति दी।

रचनाकारों की विविध और मनोहारी प्रस्तुतियों ने भाई–बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता के पवित्र रिश्ते को शब्दों में साकार कर गोष्ठी को यादगार बना दिया। सभी बहनों की सशक्त काव्य प्रस्तुतियों ने आयोजन में चार चाँद लगा दिए।

अंत में उमा मिश्रा 'प्रीति' ने अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, सभी रचनाकारों एवं उपस्थित साहित्यप्रेमियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

## भाजपा सरकार है या दुकानदार? जेपीएनआईसी के निजीकरण पर भड़के अखिलेश, लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को निजी हाथों में सौंपने के प्रदेश सरकार के फैसले पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उप्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जे.पी.एन.आई.सी. को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है।



कमीशन भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल–पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़। गौरतलब है कि प्रदेश कैबिनेट ने बीते मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत जेपीएनआईसी को संचालन और रखरखाव के लिए निजी समूह को 30 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक चयनित निजी समूह लखनऊ विकास प्राधिकरण को 831 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। जेपीएनआईसी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल रहा है और इसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक विवाद भी रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि करीब 265 करोड़ रुपए की प्रारंभिक योजना वाली यह परियोजना बाद में 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च वाली परियोजना बन गई। सरकार के मुताबिक अब इसका उद्देश्य लंबे समय से अधूरे और विवादित रहे इस परिसर को सम्मेलन, संस्कृति और खेल गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट की मंजूरी जेपीएनआईसी की संपत्ति की बिक्री के लिए नहीं है। इसके तहत इस सेंटर को 30 वर्ष की लीज पर संचालन और रखरखाव के लिए दिया जाएगा। जमीन और पूरी संपत्ति का स्वामित्व प्राधिकरण के पास ही रहेगा, जबकि चयनित बोलीदाता निविदा की शर्तों के अनुसार केंद्र के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। हालांकि, अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए इसे निजीकरण की नीति का हिस्सा बताया और भाजपा सरकार पर सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया।

## चन्द्रबदनी परिसर में कविता लेखन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ आयोजित

चन्द्रबदनी। श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, चन्द्रबदनी (नैखरी) में परिसर निदेशक डॉ महंथ मौर्य की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम–2026 के अंतर्गत ज्ञानवर्धक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कविता पाठ एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गईं।जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रश्नोत्तरी में चार टीमों ने प्रतिभाग किया। जिसमें प्रथम खुशबू एवं सृष्टि, द्वितीय काजल एवं अनामिका एवं तृतीय स्थान पर रेणुका एवं सुमन रहे।



कविता लेखन में छह विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।बी. ए. तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं खुशबू एवं सृष्टि ने कविता पाठ प्रस्तुत किया। दोनों छात्राओं ने अपनी प्रभावशाली एवं भावपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं मानवीय मूल्यों को रेखांकित किया। हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉ. सरिता द्वारा कविता पाठ के साथ कार्यक्रम का संचालन किया गया। परिसर निदेशक ने अपने संबोधन में भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत को समझने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दो दिवसीय कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. मूलचन्द्र शुक्ल ने कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं गतिविधियों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने, समझने एवं आत्मसात् करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में एंटी ड्रग सेल के नोडल अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार भट्ट द्वारा विद्यार्थियों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी ने नशे से दूर रहने तथा समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर डॉ. गुरु प्रसाद थपलियाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति रुचि एवं गौरव की भावना विकसित करने, उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।

## वरिष्ठ नागरिकों के लिए एम्स की भांति एनसीए भवन की मांग

लखनऊ (संवाददाता)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजेश पाठक को पत्र लिखकर दिल्ली एम्स की भॉति उत्तर प्रदेश में एनसीए भवन की स्थापित किए जाने की मांग की है। उन्होंने एम्स में वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए मानसिक रोग विभाग, आर्थोपेडिक विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, यूरोलॉजी विभाग और सर्जरी विभाग जैसी सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने इस आशय का पत्र श्री जगतप्रसाद नड्डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रतापराव गणपतराव जाधव राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव सचिव भारत सरकार को भी प्रेषित किया है। इं. हरिकिशोर तिवारी ने पत्र में कहा है कि अभी प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुये 70 वर्ष के ऊपर के नागरिको को भी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ कर इलाज कराने का निर्णय लिया है। पूर्व से ही बीपीएल नागरिक एंव प्रदेश के राज्य कर्मचारी तथा अब सभी शिक्षक एंव अन्य कर्मचारी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की पात्रता की श्रेणी में ले लिये गये है। परन्तु स्वास्थ्य व्यवस्था इतने अधिक नागरिको के लिये पर्याप्त नही हो पा रही है जिससे मरीज भटकते रहते हैं। विशेष कर 80 वर्ष से ऊपर कार्मिक मरीजो को भी काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अभी मैं दिल्ली एम्स में गया था। वहा पर नेशनल सेन्टर फॉर ऐजनिग स्थापित है। यह खास तौर पर वृद्धजनो हेतु समर्पित बहुमंजिला रिसर्च एण्ड ट्रीटमेन्ट के लिये बनाया गया है।

## सपा छोड़ आए 7 बागी बीजेपी की टेंशन!

### टिकट वितरण में नए और पुराने में चयन का बड़ा प्रश्न

लखनऊ (संवाददाता)। यूपी असेम्बली इलेक्शन की सरगर्मियां तेज होते ही बीजेपी के अंदर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका देकर बीजेपी का दामन थामने वाले 7 बागी विधायकों की वजह से अब बीजेपी के अपने ही खेमे में खलबली मच गई है। सपा से बगावत करके बीजेपी के पाले में आए ये सात दिग्गज नेता अपनी–अपनी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।


**उत्तर मध्य रेलवे**

निविदा सूचना सं : 7120262027 — दिनांक : 24.08.2026

**ई-निविदा सूचना**

मण्डल रेल प्रबन्धक/इंजीनियरिंग/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्यों के लिये ई-निविदाएं प्रपत्र पर दिनांक 16.09.2026 को 13:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| | |
|---|---|
| निविदा नं. : 154 | अनुमानित मूल्य (रू) : 78,26,037.05 |
| कार्यों का विवरण : मण्डल इंजीनियर/पश्चिम/प्रयागराज के अन्तर्गत कानपुर-रूरा सेक्शन में विभिन्न स्थानों पर गैंग रेस्ट शेड्स के निर्माण का कार्य। | |
| बयाने की रकम (रू) : 1,56,500.00 | कार्य समापन की अवधि : 06 माह |
| निविदा खुलने की तिथि : 16.09.2026 | |
| इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अन्तर्गत सिमिलर कार्य : कोई सिविल इंजीनियरिंग कार्य | |

नोट :- 1. आन लाइन निविदा दिनांक 16.09.2026 को 13:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। 2. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर समय 13:30 बजे टेण्डर खुलने की तिथि 16.09.2026 तक उपलब्ध है। 1974/26 (C)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONC


## नाम की माला टेरे

क्षणिक सुखों की बात निरंतर माया करती।
मृगतृष्णा का चित्र हमेशा खींचा करती।
मोहग्रस्त इन्सान सत्य से मुँह को फेरे।
हरि से होकर दूर नाम की माला टेरे।
अद्भुत सारा दृश्य है चर्चा मोह–विकास की।
बलवन्ती होती जहाँ परछाईं बस चाह की।।

सच्चाई से दूर समाहित हो ईष्या में।
मन की भोली प्यास भटकती मृगतृष्णा में।
माया ममता मोह विरह का कारण बनके।
घोट रहे हैं गला सभी को अपना कहके।
चाहत की दुनिया सदा नाता दुख से जोड़कर।
सुख की करती कल्पना हरि से नाता तोड़कर।।

**डॉ. प्रदीप चित्रांशी**
लूकरगंज, प्रयागराज

## स्वतंत्रता सेनानी वीर पदमनाथ सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई

मऊ। जनपद मऊ के परदहाँ निवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे अमर वीर पद्मनाथ सिंह जी की (113) वीं जयंती बड़े धूम–धाम व हर्षोल्लास से मनाई गई,इस सुअवसर लेखक "आशीष कुमार



सैनी" ने अमर सेनानी के संक्षिप्त जीवनी पर आकर्षक व ऐतिहासिक भाषण देकर कलेक्ट्रेट में मौजूद सभी अधिवक्ताओं को भावुक कर दिया और महापुरुष के आविर्भाव से तिरोभाव तक के सफर को विनम्रता से बताया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अमरेंद्र नाथ सिंह(सदस्य व पूर्व अध्यक्ष –बार काउंसिल उत्तर प्रदेश),ब्रिगेडियर पी.एन. सिंह,अधिवक्ता सुरेश सिंह,अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव ,किसान नेता देवप्रकाश राय,सपा नेता अनिल यादव,अशोक यादव,दीपक पाल,अजय पाल,धीरज सिंह,पंकज प्रजापति सहित तमाम अधिवक्ता व जनपदवासी मौजूद रहें,और कार्यक्रम को ऐतिहासिक,यादगार व सफल बनाए।


**उत्तर मध्य रेलवे**

ई-टेन्डर नं०: पीआरवाईजे-सिग-033-2026-27 — दिनांक: 25.08.2026

**ई-निविदा सूचना**

वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियन्ता/समन्वय/उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्य के लिये ई-निविदा निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 19.09.2026 को 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

| | |
|---|---|
| क्र. सं. 1 | निविदा नं.: पीआरवाईजे-सिग-033-2026-27 |
| कार्य का विवरण: इलेक्ट्रिकल विभाग, एसबीआर मुख्यालय सूबेदारगंज के कॉन्फ्रेंस रूम E-035 में कॉन्फ्रेंस सिस्टम का प्रावधान। | |
| अनुमानित मूल्य (₹): ₹ 17,30,612/- | बिड सिक्योरिटी (₹): ₹ 34,600/- |
| निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹): 0/- | कार्य समापन की अवधि: 12 माह |
| निविदा बन्द होने की तिथि: 19.09.2026 | |

2. निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता: निविदा प्रपत्र www.ireps.gov.in पर निविदा खुलने की तिथि से 21 दिन पहले उपलब्ध हो जायेंगे। 3. बयाने की राशि जमा करना एवं उसका रूप: निविदाओं को उपरोक्त बिड सिक्योरिटी निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन भुगतान गेटवे द्वारा की जायेगी। यदि निविदा दाता बिड सिक्योरिटी उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में जीसीसी के अनुसार जमा करते हैं तो उनका निविदा स्वीकार किया जायेगा। ... 4. निविदा खुलने का समय, तिथि तथा स्थान: निविदा पूर्व निर्धारित तिथि को 12:30 बजे या उसके बाद ई-निविदा द्वारा मण्डल रेल प्रबंधक, प्रयागराज के कार्यालय में खोली जायेगी। ... 5. निविदा की वैधता: निविदा खुलने के 60 दिन तक। 6. निविद हीलिंग हेतु रेलवे के अधिकार: रेलवे प्रशासन का, किसी भी समय बिना कारण बताये कोई एक या सारी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। 1988/26(AK)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in



**उत्तर मध्य रेलवे**

**ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ**

**उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मण्डल निविदा (आवेदन) सूचना**

आवेदन संख्या: सीएम-2/हाल्ट निविदा/आवेदन/2026 — दिनांक: 18.08.2026

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मण्डल के अंतर्गत 03 हाल्ट स्टेशनों पर (01 ठेकेदार प्रत्येक हाल्ट पर) कमीशन के आधार पर हाल्ट ठेकेदार की नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रयागराज मण्डल के अंतर्गत 03 हाल्ट स्टेशन, जिनके नाम नीचे अंकित किए गये हैं पर कमीशन के आधार पर 05 वर्ष हेतु ... आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ... www.tenders.gov.in ... www.ncr.indianrailways.gov.in ...

| निविदा/आवेदन संख्या | कार्य का नाम: प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत निम्नलिखित हाल्ट स्टेशन हेतु कमीशन बेसिस पर हाल्ट ठेकेदार नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण |
|---|---|
| 02/1 | पलरा (रूरा & रोशन मऊ के मध्य) |
| 02/2 | श्रीमद् हरिकपुरी (उमरपुर & फर्तेखपुर के मध्य) |
| 02/3 | सैफई (बैरपुर & करहल के मध्य) |

हाल्ट स्टेशन हेतु आवेदन फार्म की कीमत: रु0 100/- ...

हाल्ट स्टेशन हेतु आवेदन फार्म खरीदने की अन्तिम तिथि व समय: दिनांक 16.09.2026 को 11.00 बजे तक

हाल्ट स्टेशन हेतु आवेदन फार्म जमा करने एवं खोलने की अन्तिम तिथि/समय: दिनांक-16.09.2026 को 13.00 बजे तक ... 15.00 बजे खोले जायेंगे।

नोट :- (1) ... (2) ... रु0 5000/- (पांच हजार) ... (3) ... 1970/26(A)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

## सम्पादकीय.....

# भर्ती का धंधा

आठ लाख 60 हजार युवा, 3,539 पद, लगभग 60 करोड़ रुपये की फॉर्म फीस और 4 साल का अंतहीन इंतजार। ये महज कुछ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम पर रचे गए उस चक्रव्यूह का सीधा गणित है, जिसमें आज लाखों परिवार फंसे हुए हैं। जब देश का युवा एक अदद रोजगार के लिए दर–दर भटक रहा है, तब व्यवस्था ने उसकी उम्मीदों और मजबूरी को ही एक मुनाफे वाले व्यापार में तब्दील कर दिया है। विमर्श भले ही इसे केवल सिस्टम की नाकामी या प्रशासनिक देरी कहकर टाल दे, लेकिन इन आंकड़ों को गहराई से देखने पर एक बहुत ही सोची–समझी और क्रूर अर्थव्यवस्था का चेहरा सामने आता हैकृएक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां बेरोजगारी कोई समस्या नहीं, बल्कि मुनाफा कमाने का सबसे सुरक्षित जरिया है। बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में हो रही पीड़ा केवल कुछ आंकड़ों या तथ्यों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उस दर्द, घुटन और खामोश चीख की कहानी है, जो आज देश के हर उस छोटे से कमरे में गूंज रही है जहां एक युवा अपनी जवानी के सबसे कीमती साल महज एक वेबसाइट रिफ्रेश करने में गुजार देता है। साल 2022 में उत्तरप्रदेश के युवाओं ने जब फॉर्म भरा था, तो उन्होंने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं जमा किया था, बल्कि अपने बूढ़े होते मां–बाप की आखिरी उम्मीदें और अपनी रातों की नींदें गिरवी रखी थीं। आज चार साल बाद, वह इंतजार एक ऐसे नासूर में बदल चुका है, जिसका इलाज इस व्यवस्था के पास शायद है ही नहीं। सरकारी भर्तियों में यह सालों की देरी महज लाल फीताशाही का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह युवाओं के मनोविज्ञान को तोड़ने का एक क्रूर हथियार है। जब एक 23 साल का ऊर्जावान युवा नौकरी की तैयारी में बैठे–बैठे 27 साल का हो जाता है, तो उसका आत्मविश्वास धीरे–धीरे खत्म होने लगता है। इस प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य यह है कि जब युवा पूरी तरह से थक–हार जाए, तो वह अपने वजूद को बचाने के लिए 4,000 रुपये की ट्यूशन या किसी डिलीवरी–ऐप की 10,000 रुपये की नौकरी को ही अपनी नियति मान ले। एक टूटा हुआ और थका हुआ युवा कभी अपने हकों के लिए सत्ता से तीखे सवाल नहीं पूछता। बेरोजगारी आज के समय में बिना किसी जोखिम वाला एक ऐसा व्यापार बन गई है, जिसमें व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं है। परीक्षा फॉर्म के नाम पर ली जाने वाली फीस असल में युवाओं की उम्मीदों पर लगाया गया श्होप टैक्सश यानि श्उम्मीद का करश है। उपरोक्त परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा युवाओं से औसतन 700 रुपये प्रति फॉर्म के हिसाब से लगभग 60 करोड़ रुपये तो सीध ो तौर पर वसूले गए, लेकिन लूट का यह गणित यहीं खत्म नहीं हुआ। इसमें वो खर्चे तो जोड़े ही नहीं गए जो एक बेरोजगार छात्र हर फॉर्म के साथ अपनी जेब से वहन करता हैकृदस्तावेजों की फोटोकॉपी, साइबर कैफे का चार्ज, फॉर्म भेजने के लिए पोस्टल या स्पीड–पोस्ट के खर्चे और परीक्षा केंद्रों तक दर–दर भटकने का किराया। अगर इन श्छिपे हुए खर्चोंश को भी जोड़ लिया जाए, तो छात्रों की जेब से निकला यह आंकड़ा अरबों में पहुंच जाएगा। जब परीक्षाएं 3 से 4 साल तक टलती हैं, तो फॉर्म के नाम पर जमा इन करोड़ों रुपयों पर सरकारी खजाने या एजेंसियां बैंकों से भारी–भरकम ब्याज खाती हैं। यह दुनिया का शायद इकलौता ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां गरीब ग्राहक (युवा) कर्ज लेकर पैसा पहले देता है, सालों इंतजार करता है और बदले में कुछ न मिलने पर वह उपभोक्ता अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता। बेरोजगारी के मूल कारणों को सुलझाने के बजाय, व्यवस्था अक्सर तात्कालिक हेडलाइन मैनेजमेंट का सहारा लेती है। हालिया बजट में घोषित इंटर्नशिप योजना इसका एक सटीक उदाहरण है। कागजों पर दावा किया जाता है कि लाखों युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में काम सिखाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन कंपनियों के पास हर साल लाखों नए युवाओं को काम सिखाने का न तो बुनियादी ढांचा है और न ही संसाधन। ऐसी योजनाएं जमीन पर रोजगार पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि केवल न्यूज साइकिल को मैनेज करने के लिए बनाई जाती हैं। जीवन के जिस पड़ाव पर शादी और फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, वहां वह अपनी बेरोजगारी की ग्लानि तले घुट रहा है। जब एक युवा अपने माता–पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने और उनकी दवाइयों का खर्च उठाने के बजाय, 28–30 साल की उम्र में भी उनसे ही पैसे मांगने को मजबूर हो, तो वह किसी नए रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत कैसे करेगा? यह क्रूर व्यवस्था केवल युवाओं की नौकरियां ही नहीं छीन रही है, बल्कि पूरी–की–पूरी पीढ़ी को पारिवारिक और सामाजिक रूप से अपाहिज बना रही है। एक राज्य का बजट यह स्पष्ट कर देता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं, लेकिन पुलिस विभाग में लाखों भर्तियां तेजी से पूरी जाती हैं, तो यह एक गहरी कंट्रोल थ्योरी की ओर इशारा करता है। एक शिक्षक का काम ऐसे नागरिक तैयार करना है जो तर्क करें, सवाल पूछें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। वहीं, पुलिस बल का उपयोग व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब सालों से इंतजार कर रहा हताश युवा सड़कों पर अपने हक के लिए उतरता है,

तो उसे चुप कराने के लिए विचारों की नहीं, बल्कि लाठियों की आवश्यकता पड़ती है।

# बांग्लादेश मक्का समझौते में शामिल होगा?

असद मिर्जा

बंग्लादेश का कहना है कि वह सऊदी–तुर्की–पाकिस्तान रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए श्खुलाश है। यह शब्द चयन बहुत कुछ कह जाता है। यह हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं भी नहीं है– और भारत के लिए, यह दो वर्षों से चल रहे एक बदलाव की पुष्टि करता है। कूटनीति में शब्दों का महत्व होता है, और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने अपने शब्द सोच–समझकर चुने। यह पूछे जाने पर कि क्या ढाका मक्का संयुक्त रक्षा समझौते– जो समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को हस्ताक्षरित किया– में शामिल होगा, कबीर ने नहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस विकल्प पर विचार करेगा। यह उस देश की भाषा है जो दरवाजा अधखुला रख रहा है, बंद नहीं कर रहा। समझौता अपने आप में स्पष्ट है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने प्रतिबद्धता जताई है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा – यह एक तरह का आर्टिकल 5 जैसा प्रावधान है, जो पिछले सितंबर हस्ताक्षरित सऊदी–पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर आध ाारित है। मिस्र इस विचार पर बिना प्रतिबद्ध हुए बहस कर रहा है, क्योंकि उसे ग्रीस और साइप्रस के साथ अपनी उलझनों की चिंता है। बांग्लादेश अब सार्वजनिक रूप से रुचि जताने वाला दूसरा देश है। मुश्किल से दो हफ्ते पुराने गुट के लिए, यह दिल्ली में किसी भी अनुमान से कहीं तेज खिंचाव है। यह सब अचानक नहीं हुआ। बांग्लादेश में तुर्की की मौजूदगी मक्का समझौते के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से बढ़ रही थी। अंकारा अब ढाका को सैन्य उपकरण आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। पिछले साल के अंत में, पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशी कर्मियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया– 1971 के बाद पहली ऐसी व्यवस्था, जो उस देश में स्पष्ट महत्व रखती है जिसका स्थापना–युद्ध ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था। बताया जाता है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने जमात–ए–इस्लामी के ढाका कार्यालय के नवीनीकरण को वित्तपोषित किया है और इस्लामवादी नेताओं की तुर्की के हथियार सुविधाओं की यात्राओं की व्यवस्था की है। विवरण चाहे जो भी हों, पैटर्न स्पष्ट हैरू अंकारा ने दो वर्षों में ढाका में ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिन्हें एक रक्षा समझौता महज औपचारिक रूप दे रहा है। यही कारण है कि भारतीय टिप्पणीकार अब पाकिस्तान को अकेला कारक मानने के बजाय तुर्की को अधिक तत्काल समस्या के रूप में देखने लगे हैं। कुछ विश्लेषकों का यह कहना कि तुर्की दक्षिण एशियाई विमर्श में श्नया ईरानश बनता जा रहा है, यह दर्शाता है कि दिल्ली का रणनीतिक हलका अंकारा के बारे में किस तरह बात कर रहा है– एक स्वतंत्र स्वभाव वाले दूर के नाटो सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि भारत के पूर्वी पड़ोस को नया आकार देने वाले सक्रिय खिलाड़ी के रूप में। यह चिंता की एक नई श्रेणी है, जो दशकों से चली आ रही भारत–पाकिस्तान की सोच में ठीक से फिट नहीं बैठती। यह पुरानी झुंझलाहटों से ज़्यादा क्यों चुभता है, इसकी वजह भूगोल है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, ऐसी सीमा के पार जिसे भारत ने पचास वर्षों से रोकथाम, कूटनीति और महज जान–पहचान के जरिए संभालना सीखा है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में है, भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से के चारों ओर लिपटा हुआरू चिकन नेक कॉरिडोर, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है, और विद्रोह–प्रवण राज्यों की एक पट्टी जो शांत बने रहने के लिए ढाका के सहयोग पर निर्भर रही है। भारत ने इस मोर्चे के अमित्र हो जाने के लिए गंभीर आकस्मिक योजना नहीं बनाई, क्योंकि शेख हसीना के पंद्रह वर्षों के शासन में उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगस्त 2024 में हसीना की सत्ता से बेदखली ने इस धारणा को रातोंरात खत्म कर दिया।चाहे अंकारा, इस्लामाबाद और ढाका की अंतरिम सरकार विशेष रूप से भारत के खिलाफ समन्वय कर रहे हों या नहीं, व्यावहारिक नतीजा भारत की पूर्वी सीमा पर एक ऐसी सुरक्षा संरचना है जिसे भारत ने न डिजाइन किया, न नियंत्रित करता है, और न ही किसी अलग युग के लिए बने औजारों से आसानी से रोक सकता है। दिल्ली की प्रतिक्रिया अब तक संयमित रही है, और यह संयम जानबूझ कर है, निष्क्रियता नहीं। ज़्यादा शोर मचाना ढाका और अंकारा को एक प्रचार जीत सौंप देगा, और पाकिस्तानी टिप्पणीकारों द्वारा पहले से चलाए जा रहे श्घेराबंदीश के आख्यान को बल देगा। शांत कूटनीति विकल्पों को सुरक्षित रखती हैरू बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ निरंतर जुड़ाव, खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध– जिनके पास एक मुखर अंकारा के खिलाफ हेजिंग करने के अपने कारण हैं। अति–प्रतिक्रिया न करने का भी एक तर्क है। मक्का समझौते की सारवत्ता उसकी भाषा से कहीं पतली है। नाटो का आर्टिकल 5 इसलिए काम करता है क्योंकि उसके पीछे एकीकृत कमान संरचनाएं, संयुक्त अभ्यास, और सात दशकों का संस्थागत विश्वास है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उनके पास तीन अलग–अलग खतरे की धारणाएं हैं – रियाद को ईरान की चिंता, इस्लामाबाद भारत पर केंद्रित, अंकारा पूर्वी भूमध्य सागर पर– जो किसी साझा शत्रु से ज़्यादा सुन्नी एकजुटता से एक साथ आए हैं। साझा पहचान पर बने समझौते, साझा खतरे पर बने समझौतों की तुलना में असली संकट की परीक्षा में अक्सर टूट जाते हैं। मिस्र की झिझक खुद इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय खिलाड़ी यहां सिर्फ संभावना नहीं, सीमाएं भी देख रहे हैं। लेकिन भारत यह मानकर योजना नहीं बना सकता कि समझौता कमजोर ही बना रहेगा। उसे इसके लिए योजना बनानी होगी कि अगर बांग्लादेश औपचारिक रूप से शामिल हो जाए, अगर ढाका को तुर्की की हथियार बिक्री और गहरी हो जाए, अगर पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षक एक बार की पहल के बजाय स्थायी उपस्थिति बन जाएं, तो क्या होगा। इनमें से हर एक अकेले प्रबंधनीय है। लेकिन साथ मिलकर, ये एक ऐसे पूर्वी मोर्चे का वर्णन करते हैं जो चुपचाप एक तय सवाल बनना छोड़ चुका है। बड़ा सबक भारत की अपनी पड़ोस–नीति की सोच के बारे में है। वर्षों तक, दिल्ली की क्षेत्रीय रणनीति यह मानकर चलती रही कि पाकिस्तान ही मुख्य शत्रुतापूर्ण खिलाड़ी बना रहेगा और बाकी सब– बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका – भूगोल और आर्थिक निर्भरता के चलते स्वाभाविक रूप से भारत के प्रभाव–क्षेत्र में बने रहेंगे।

यह धारणा अब स्पष्ट रूप से टूट रही है। छोटे देश यह समझ रहे हैं कि उनके पास अन्य विकल्प भी हैं, और वे विकल्प – विशेष रूप से तुर्की– उनमें से एक बनने के लिए राजनीतिक पूंजी निवेश करने को तैयार हैं। कबीर का सोच–समझकर दिया गया जवाब गठबंधन की घोषणा नहीं है। यह एक देश द्वारा यह परखना है कि विकल्प रखने से कितना लाभ उठाया जा सकता है– और यही बात दिल्ली को किसी औपचारिक हस्ताक्षर से कहीं ज़्यादा चिंतित करनी चाहिए। यहां एक व्यापक पैटर्न भी है, जिसे भारत की पश्चिम एशिया नीति ने समझने में देर की है। दिल्ली की खाड़ी रणनीति काफी हद तक यूएई और इजराइल पर टिकी रही है, जो मुख्यतरू अमेरिका के साथ ढ22 समूह के माध्यम से चलती है। इस ढांचे ने यह मान लिया था कि खाड़ी का केंद्र–बिंदु लगभग एक दशक से जहां रहा है, वहीं बना रहेगा। मक्का समझौता कुछ और ही संकेत देता है। सऊदी अरब अब तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक रक्षा संरचना गढ़ रहा है– दो ऐसे देश जिन्हें भारत ऐतिहासिक रूप से दूरी पर रखता आया है– जिसका अर्थ है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसके प्रवासी समुदाय के हित, और उसके व्यापार मार्ग, सभी एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरते हैं जो भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति माने बिना ही और जटिल हो गया है। आर्थिक साझेदारी रणनीतिक प्रासंगिकता के बराबर नहीं है, और अब इन दोनों के बीच की खाई को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ जवाबी बयानबाजी या संयमित कूटनीति तक सीमित नहीं रह सकती। इसके लिए बांग्लादेश को, और उसके पीछे चल रहे व्यापक पश्चिम एशियाई पुनर्गठन को, एक गुजरती परेशानी नहीं बल्कि एक सजीव रणनीतिक समस्या के रूप में देखना जरूरी है। इसका अर्थ है, यूएई–इजरायल धुरी से आगे बढ़कर खाड़ी साझेदारों के साथ गहरी सुरक्षा जुड़ाव, चुनावों के अपने आप सब कुछ सुलझाने का इंतजार करने के बजाय ढाका की अंतरिम सरकार तक निरंतर पहुंच, और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को जाने–पहचाने पाकिस्तान वाले खांचे में समेटने के बजाय उनका स्पष्ट आकलन। यह क्षेत्र दिल्ली के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं कर रहा, और, ऐसा लगता है, बांग्लादेश भी नहीं।

# नीति आयोग की रिपोर्ट और 2047 का भारत

प्रधानमंत्री मोदी आज के हालात सुधारने की जगह या तो हजार साल पुराने भारत की बात करते हैं या फिर 2047 की बात करते हैं। योजना आयोग की जगह उन्होंने जो नीति आयोग बनाया है, उसकी भी हालिया रिपोर्ट रिइमैजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047 है, यानी श्2047 में विकसित भारत के लिए कौशल विकास (स्किलिंग) की पुनर्कल्पनाश। मोदी चाहते हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, देश की मौजूदा कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली में नए सिरे से बड़े और प्रभावी बदलाव किया जाए। इसी पर नीति आयोग ने पूरी रिपोर्ट बना दी है कि किस तरह कौशल विकास स्कूलों से शुरु हो, डिजिटल स्किल्स पासपोर्ट हो यानी अलग–अलग जगहों से हासिल स्किल्स और ट्रेनिंग को डिजीटली दर्ज किया जाए, ताकि नौकरी या शिक्षा में उसका उपयोग हो, आईटीआई और पॉलिटेक्निक को स्थानीय उद्योगों के मुताबिक लचीला बनाया जाए, महिलाओं के लिए रोजगार के मौके और स्किल ट्रेनिंग के लिए लचीली व्यवस्था हो। कई तरह के सुझाव नीति आयोग की रिपोर्ट में हैं। लेकिन इन का जमीन असर पर तो तभी दिखाई देगा, जब आज के हालात सुधारे जाएं। क्योंकि नरेन्द्र मोदी ने वादा किया था कि हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे। इस हिसाब से अब तक 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन नीति आयोग बता रहा है कि भारत की करीब आधी आबादी तो मजदूरी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 65.4 करोड़ (यानी कुल 145 करोड़ की 45. 1 प्रतिशत) आबादी मजदूरी करती है। इनमें 8.4 प्रतिशत नौकरी, रोजगार, स्किल ट्रेनिंग आदि के जो आंकड़े नीति आयोग ने पेश किए हैं, उनमें मोदी सरकार की असलियत सामने आ गई है कि पिछले बारह सालों में उसने देश को कितना पीछे धकेल दिया है। 2014 में कार्यबल तो अपना काम करने वाले (स्वरोजगार) हैं, 21.7 प्रतिशत लोगों के पास नियमित वेतन वाली नौकरी है, जबकि 19.8 प्रतिशत लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। वहीं 79.6 करोड़ यानी 54.9 प्रतिशत लोग मजदूर वर्ग से बाहर हैं। इनमें 29.1 करोड़ छात्र हैं, वहीं 59 साल से अधिक या 5 साल से कम उम्र के 27 करोड़ लोग हैं और 14.7 करोड़ अन्य शामिल हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में युवाओं के बारे में जो बताया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है, नीति आयोग बताता है कि करीब साढ़े आठ करोड़ युवा न पढ़ रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं, न किसी किस्म का प्रशिक्षण ले रहे हैं। नीति आयोग का अनुमान है कि 15 से 29 साल की उम्र के 8. 7 करोड़ युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न ही नौकरी या ट्रेनिंग में हैं। इनमें से लगभग 88 प्रतिशत युवा घर के कामों में लगे हैं। साथ ही, युवाओं में बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत है, जिनमें युवतियों की संख्या 19. 5 प्रतिशत तक है। जिस देश में करीब 9 करोड़ युवा न पढ़ रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं न किसी तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं, उस देश के लिए कैसा खतरनाक भविष्य तैयार हो रहा है, यह समझना कठिन नहीं है। युवा शक्ति के दम पर ही भविष्य के सपने बुने जाते हैं। लेकिन खाली बैठे हताश नौजवान क्या सपनों को जीने लायक बच रहे हैं, यह सवाल अब मोदी सरकार से किया जाना चाहिए। अच्छी बात है कि देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षा व्यवस्था की खामियां, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में भर्ती की धांधलियां ऐसे बेहद जरूरी विषयों पर आम जनता के बीच चर्चा तेज हो गई है। मई में नीट का पेपर लीक होने के बाद शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों पर सवाल उठने शुरु हुए और अब अगस्त खत्म होने तक ये सवाल खत्म नहीं हुए हैं, दबाए नहीं जा सके हैं बल्कि तेज होते जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे तो पूरी स्पष्टता के साथ अपनी बात सामने रख ही रहे हैं, उनके अभिभावक भी अब उनके साथ उठ खड़े हुए हैं। इसकी बेचैनी सत्तारुढ़ वर्ग में साफ देखी जा सकती है। चाहे राजस्थान में स्कूलों में वीडियो बनाने या तस्वीरें लेने पर प्रतिबंध का मामला हो, या उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का यह दावा करना कि उनके प्रोजेक्ट अलंकार में सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारा गया है और जो जर्जर हाल वाली तस्वीरें सामने आई हैं, वो पिछली सरकारों का स्मारक हैं। ऐसी बातें ही बता रही हैं कि सरकार अब युवाओं के भविष्य से जुड़े इस अहम मुद्दे को नजरंदाज नहीं कर सकती है, न ही किसी तरीके से सवालों को उठने से रोक सकती है।

# बीमार हैं स्कूल

देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जिस देश में एक लाख स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हों, मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हो, वहां पढ़ाई का स्तर क्या होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। कुछ स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, कुछ पेड़ तले व बरामदों में– तो सवाल स्वाभाविक है कि सुधार क्यों नहीं होता? आखिर इन स्कूलों का सुधार हमारे नीति–नियंताओं की प्राथमिकताओं में क्यों नहीं होता? जिस शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी फौज तैनात है, उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? अब भले ही सरकारी स्कूलों को सीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया हो, लेकिन इससे पहले ही देश के कई भागों में छात्र स्कूलों में सुध ाार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। विडंबना यह है कि इन स्कूलों पर ग्रामीण, समाज के वंचित वर्गों, श्रमिकों व गरीब बच्चों की निर्भरता अधिक होती है, फलतरू उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी जाती है। यदि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों के लिये सरकारी स्कूलों में भर्ती अनिवार्य कर दी जाती तो शायद इन स्कूलों के दिन फिर जाते। सरकारी स्कूलों का सच किसी से छिपा नहीं है। नीति आयोग के हालिया आंकड़े इस सच को अनावृत करते हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में पूरे देश में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। साथ ही इसी अवधि में सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल भी 83 हजार से घटकर 79 हजार रह गये हैं। स्कूलों में छात्रों के दाखिले में कमी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुनाफा कमा रहे निजी स्कूलों का कुनबा लगातार बढ़ ही रहा है। उनकी संख्या अब 2.9 लाख से बढ़कर 3.4 लाख के करीब हो गई है। यह एक हकीकत है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों की जो फिक्र सामने आ रही है, उसके निहितार्थ समझना कठिन नहीं है। इन दलों की सरकारों के दौरान भी इन स्कूलों की दिशा–दशा में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। चिंता इस बात को लेकर है कि इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, कहीं उसके चलते सुधार के विमर्श पर आंच न आए। सही मायने में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होना चाहिए। इसमें शासन, प्रशासन, पक्ष–विपक्ष और नागरिकों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। नीति–नियंताओं को सोचना चाहिए कि अभिभावकों से मोटी फीस लेने वाले निजी स्कूल क्यों फल–फूल रहे हैं?

सरकारी स्कूलों के पास भवन हैं, पर्याप्त जगह है, सम्मानजनक पगार वाले शिक्षक हैं और सरकारी तंत्र का समर्थन है, तो ये स्कूल पनप क्यों नहीं रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में पानी, बिजली, बेंच, टेबल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ा नहीं कराई जा रही हैं? बल्कि सुधारों के बजाय शिक्षकों की नियुक्ति में राजनेताओं की धांधली की खबरें अकसर मीडिया में तैरती रहती हैं। विडंबना देखिये कि पढ़ाई–लिखाई के लिये अनुकूल वातावरण की मांग को लेकर राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं।

# सबके हिस्से का पानी (लघु कथा)

दो आबादियाँ पहाड़ों की क़तार से बंटी थीं। एक बस्ती की जानिब झरना गिरता था और दूसरी तरफ़ के लोग पहाड़ पर चढ़ कर पानी लाते थे। उस पानी की कमी वाली बस्ती में एक पागल था जिसे प्यास बहुत लगती थी। वह डोलचे में अपने लिए पहाड़ पर से पानी भर ले आता था।

उसे धूप भी बहुत लगती थी इस लिये जब वह पहाड़ पर चढ़ता तो बड़बड़ाता ष्पहाड़ पर चढ़ो तो धूप मार डालती है न चढ़ो तो प्यास मार डालेगी! उस पत्थर की दीवार कोई तोड़ क्यो नहीं डालता जो बरसों से पानी को हमारी तरफ़ आने रोके है,पता नहीं लोग अपने हिस्से का पानी कब हासिल करना चाहेंगेष

एक रोज़ जब वह पानी लाने के लिए बेतहाशा बड़बड़ाते और चिल्लाते हुए पहाड़ पर चढ़ रहा था तो किसी ने छेड़ दिया ष्तुम खुद पत्थर की दीवार तोड़ कर सब के हिस्से के पानी का इंतेज़ाम क्यों नहीं कर देतेष। तंज़ सुनते ही पागल डोलचा फेंक कर पहाड़ से उतर पड़ा। फिर लोगों ने देखा कि वह एक कुदाल कांधे पर रखे बड़बड़ाते चिल्लाते हुए पहाड़ पर चढ़ा जा रहा है ष्अब मैं पहाड़ से नीचे आऊँ या न आऊँ मगर सब के हिस्से का पानी आयेगा

सारा दिन वह पागल पानी पी पी कर धूप में पहाड की उस भारी चट्टान पर पूरी ताक़त से कुदाल मारता रहा जो पानी के रास्ते में दीवार बनी थी। शाम ढल कर जब रात हो गई और सन्नाटा हर तरफ़ पसर गया तब भी पागल की कुदाल का शोर बस्ती मे साफ़ सुनाई देता रहा।

दूसरे दिन सुब्ह के वक़्त पानी लेने वाले जब पहाड़ पर पहुँचे तो उन्होंने उस थकन से चूर हो चुके पागल को बहुत रोका मगर उसे तो धुन सवार थी।उसने लोगों का दिया हुआ खाना खाने से भी यह कह कर इंकार किया कि ष्अब पानी ही मेरा खाना हैष

उस रात पागल की एक भयानक चीख के बाद कुदाल के चलने की आवाज़ का आना बन्द हो गया और अचानक पानी के बहाव की भैरवी ने सारी बस्ती को जगा दिया। घरों से निकल कर बस्ती वालों ने देखा कि उनके हिस्से के पानी पहाड़ से नीचे उतर चुका है।

अनवार अब्बास नक़वी

# अगली फिल्म 'गांधारी' पर क्या बोलीं तापसी? 'लापता लेडीज' फेम छाया कदम का मिलेगा साथ, बोलीं– 'यह सफर मेरे लिए..'

तापसी पन्नू की फिल्म 'गांधारी' इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म में छाया कदम भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने अपने किरदार के लिए तैयारी पर खुलकर बात की। फिल्म 'गांधारी' में अपने किरदार के बारे में छाया कदम ने काफी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि अपने किरदार को आत्मसात करने के लिए उन्हें कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। छाया ने कहा३ इस किरदार के लिए मुझे बंगाली सीखने का मौका मिला। मुझे यह अनुभव बेहद पसंद आया। इस भाषा के होने से किरदार में एक नया आयाम जुड़ गया। यह सफर मेरे लिए और भी यादगार बन गया। फिल्म 'गांधारी' में छाया ने बंगाली भाषी महिला का किरदार निभाया है। अभिनेत्री तापसी पन्नू को ने भी फिल्म पर काफी कुछ कहा। एक्ट्रेस ने कहा, 'गांधारी फिल्म देखते समय बानी की हार न मानने की भावना मेरे मन में हमेशा बसी रही, भले ही परिस्थितियाँ उसके विपरीत थीं। इस भूमिका के लिए शारीरिक रूप से काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसकी दृढ़ता, दृढ़ विश्वास और अटूट हौसला ही वह चीज थी जिसने मुझे सचमुच मंत्रमुग्ध ा कर दिया। फिल्म गांधारी का निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। फिल्म में श्वक सिंह और स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। 'लापता लेडीज' के बाद छाया कदम को एक बार फिर दमदार अंदाज में देखा जा रहा है। विषय अलग है, मगर बात धर्म की है, तो इस फिल्म की थीम को महाभारत से जोड़ा गया है। फिल्म 03 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

# अपनी फिल्म टॉक्सिक का पहला शो देखने पहुंचीं हुमा कुरैशी, सिनेमाघर में जाने से पहले किया यह काम

इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक श्टॉक्सिकश आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। पहले दिन पहला शो देखने के लिए कई दर्शक उत्साहित नजर आए। कई दर्शक ढोल–तमाशों के साथ सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए पहुंचे। इस बीच हुमा कुरैशी भी अपनी फिल्म देखने के लिए मुंबई के एक सिनेमाघर पहुंचीं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हुमा कुरैशी अपनी फिल्म टॉक्सिक का पहला शो देखने के लिए मुंबई के एक सिनेमाघर में पहुंचीं। सिनेमाघर में जाने से पहले उन्होंने काली और सफेद ड्रेस में कैमरे के सामने पोज दिए। उन्होंने काले चश्मे से अपने लुक को पूरा किया। आपको बता दें कि हुमा कुरैशी ने फिल्म फिल्म टॉक्सिक में एलिजाबेथ का किरदार निभाया है। बताया जाता है कि यह किरदार शांत और शालीन है। उनके अलावा फिल्म में यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और नयनतारा हैं। इसे गीतू मोहनदास ने निर्देशित किया है। टॉक्सिक पब्लिक रिव्यूरू तीन घंटे की फिल्म सजा या मजा? 'टॉक्सिक' देखकर क्या बोले दर्शकय यश के लिए कह डाली यह बात फिल्म देखकर कई यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ यूजर्स को फिल्म बोर लगी है, तो वहीं कुछ यूजर्स ने बताया है कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। एक यूजर ने फिल्म को श्सीधे–सीधे टॉर्चरश बताया और कहा कि यह अनुभव 90 मिनट का ट्रेलर देखने जैसा था। फिल्म एक सीन से दूसरे सीन तक बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। वहीं एक दूसरे यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा डार्क, रॉ और कभी न भूलने वाला। टॉक्सिक में यश का अंदाज एकदम अलग लेवल का है। एक ऐसा विजुअल और साउंड का जबरदस्त अनुभव जो बड़े पर्दे पर ही देखा जाना चाहिए। जबरदस्त क्रेज। हुमा कुरैशी के काम की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म पूजा मेरी जान का हिस्सा होंगी। इसके अलावा वह फिल्म श्गुलाबीश का भी हिस्सा होंगी। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म श्बेबी डू डाई डूश बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। टॉक्सिक से लोगों को काफी उम्मीदें हैं।

# तिरंगा प्रेरित ड्रेस पहनने पर जमकर ट्रोल हुईं उर्वशी रौतेला, बात बढ़ने के बाद दी सफाई, कही ये बात

मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में उर्वशी ने तिरंगे से इंस्पायर्ड गाउन पहना था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके आउटफिट को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इससे भारतीय झंडे के नियमों का उल्लंघन होता है। अब उर्वशी ने इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 में पहना था खास गाउन मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले 23 अगस्त को हुआ था। उर्वशी रौतेला इस इवेंट में जज के तौर पर शामिल हुई थीं। उनके साथ भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा, पर्यावरणविद और फिल्म प्रोड्यूसर प्रज्ञा कपूर और पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स व मिस यूनिवर्स रनर–अप सेलिना जेटली भी जजिंग पैनल का हिस्सा थीं। इस खास मौके पर उर्वशी ने तिरंगे से प्रेरित एक गाउन पहना। उनका यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसी के साथ विवाद भी शुरू हो गया। उर्वशी के आउटफिट की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से जोड़कर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा कि भारतीय झंडे को कपड़ों की तरह पहनना या ड्रेस पर सीध ो प्रिंट करना फ्लेग कोड ऑफ इंडिया के तहत अनुमति नहीं है। वहीं, कुछ लोगों ने इसे देश का अपमान तक बताया। एक यूजर ने दावा किया कि राष्ट्रीय ध्वज को ड्रेस का हिस्सा बनाना या उसे जमीन पर छूने देना कानून के तहत गलत है। हालांकि, इन दावों के बीच उर्वशी ने साफ किया है कि उनका गाउन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की हूबहू कॉपी नहीं था।

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उर्वशी ने कहा कि वह अपने देश को सिर्फ अपनी नागरिकता के तौर पर नहीं देखतीं, बल्कि भारत को अपनी पहचान का हिस्सा मानती हैं। उन्होंने बताया कि वह ऐसा आउटफिट पहनना चाहती थीं, जो यह दिखाए कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है। उर्वशी ने कहा, 'मैं अपने देश को सिर्फ एक राष्ट्रीयता के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पहचान के हिस्से के रूप में अपने साथ लेकर चलती हूं।' उन्होंने आगे कहा कि उनके गाउन में रंगों की प्लेसमेंट, डिजाइन, कढ़ाई, डिटेलिंग और पूरा लुक फैशन के हिसाब से तैयार किया गया था। उनका मकसद सिर्फ तीन रंगों को ड्रेस पर लगाना नहीं था, बल्कि देश से जुड़ी भावना को एक आर्टिस्टिक अंदाज में दिखाना था। उर्वशी ने विवाद पर जवाब देते हुए कहा कि उनके गाउन और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच कई साफ अंतर हैं। उन्होंने कहा, 'सबसे जरूरी बात यह है कि यह गाउन राष्ट्रीय ध्वज की हूबहू कॉपी नहीं है। यह तिरंगे के रंगों से प्रेरित एक कॉउचर डिजाइन है।'

# राज फिल्म की इस अभिनेत्री को पहचानना हुआ मुश्किल, कभी पर्दे पर बिखेरा था हुस्न ... 23 साल से लापता चकाचौंध से दूर करती हैं

विक्रम भट्ट द्वारा बनाई गई साल 2002 में रिलीज हुई हिंदी सिनेमा की मशहूर हॉरर–थ्रिलर फिल्म राज आज भी दर्शकों में काफी लोकप्रिय है। विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में डीनो मोरिया और बिपाशा बसु मुख्य भूमिकाओं में नजर आये थे। वहीं, फिल्म में मालिनी नाम की रहस्यमयी भूतनी का किरदार निभाकर अभिनेत्री मालिनी शर्मा ने भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था। लेकिन अब 24 साल बाद मालिनी शर्मा फिल्मों की दुनिया से काफी समय से दूर हैं। ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि राज की ये खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री आजकल कहां हैं, क्या कर रही हैं और इतने सालों में उनका लुक कितना बदल गया है ? आइए जानते हैं– फिल्म राज से एक रात में लोकप्रियता हासिल करने वालीं अभिनेत्री मालिनी शर्मा ने अचानक बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली थी। लंबे समय से लाइमलाइट से दूर रहीं मालिनी को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह इन दिनों पुणे के ह्याद्रि पहाड़ियों के शांत इलाके में अपना जीवन बिता रही हैं। चमक–दमक से दूर मालिनी ने प्रकृति के करीब एक अलग जिंदगी चुनी है। वह पहाड़ी क्षेत्र में खेती–किसानी भी करती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके एक अनदेखे वीडियो में वह अपनी इस नई जिंदगी के बारे में बात करती नजर आई हैं। इतना ही नहीं, अभिनेत्री वहां अपना फार्मस्टे भी चलाती हैं, जहां आने वाले मेहमानों के लिए वह खुद खाना भी बनाती हैं। मालिनी शर्मा की हालिया तस्वीरों और वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि समय के साथ उनका लुक काफी बदल गया है और अब वह पहले जैसी नजर नहीं आतीं। 52 साल की मालिनी इन दिनों अपनी अलग और सादगी भरी जीवनशैली को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि फिल्म राज में अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों का ध्यान खींचने वाली मालिनी एक दिन ग्लैमर और भीड़भाड़ से दूर एकांत और शांत जिंदगी को चुन लेंगी। आज वह चकाचौंध से दूर अकेले रहकर प्रकृति के करीब अपना जीवन बिता रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से मालिनी शर्मा के दूर होने के पीछे उनकी निजी जिंदगी को भी एक अहम वजह माना जाता है। मालिनी ने फिल्म तुम बिन से पहचान बनाने वाले अभिनेता प्रियांशु चटर्जी से शादी की थी। हालांकि, उनका यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और दोनों ने बाद में तलाक ले लिया। बताया जाता है कि इस रिश्ते के टूटने का असर मालिनी पर काफी गहरा पड़ा, जिसके बाद वह लंबे समय तक सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आईं और ध ीरे–धीरे फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर हो गईं।

# अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बढ़ा रहे है बीमारियों का जोखिम! इन हेल्दी ऑप्शन्स से मिटाएं

चिप्स, नमकीन, कोल्ड्रिंक्स, फ्रोजन पिज्जा या फ्रोजन फूड्स,आइसक्रीम आदि जैसी चीजों लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। एक स्टडी के हिसाब से भारत में बीते एक दशक में अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फूड की बिक्री 13.37 फीसदी सालाना की दर से बढ़ी है। पर ये सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। अल्ट्रा– प्रोसेस्ड फूड्स में प्रोसेस्ड कार्ब्स और कैलोरीज ज्यादा होती हैं और कई बीमारियां जैसे की मोटापा, हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज आदि बीमारियों का खतरा रहता है। इन फूड्स का हाई सोडियम कंटेंट खाने के बाद ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कारण बनता है। बीमारियों से बचने के लिए इन फूड्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे पसंदीदा अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फूड्स का विकल्प खोजना है। अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां कुछ ऑप्शन हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं.

...

आइसक्रीम की जगह दही

अगर आप आइसक्रीम के बजाए डॉर्क चॉकलेट में लिपटे फ्रूटी फ्रोजन योगर्ट या बनाना पॉप ट्राई कर सकती हैं। आप आइसक्रीम के अलावा फ्रोजन डेसर्ट से अपनी क्रेविंग पूरी कर सकते हैं। अगर आप कुछ मलाईदाक खाने के मूड में हैं तो अपने पसंदीदा दही के साथ कटे हुए फल मिलाएं और इसे कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रख दें। अगर आपको अपने जीवन में बस थोड़ी सी चॉकलेट की जरूरत है तो फ्रोजन केले को 80 प्रतिशत पिघली हुई चॉकलेट में डुबोएं।

मिल्कशेक की जगह स्मूदी

मिल्कशेक से बचें और सीधे होममेड स्मूदी का विकल्प चुनें। मीठे फलों का हेल्दी ऑप्शन चुनें जब आपको मिठाई खाने की इच्छा हो, हालांकि हमारी पीनट बटर ओट स्मूदी प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरी हुई होती है, तो हमेशा क्लासिक मिल्कशेक की जगह स्मूदी का सेवन करें।

कैंडी की जगह डॉर्क चॉकलेट

अगर आप मीठी कैंडी खाना का मन करता है तो डॉर्क चॉकलेट कैंडी एक अच्छा ऑप्शन है। डार्क चॉकलेट में कई पोषक तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के सबसे अच्छे स्नोतों में से एक है।

शुगरी ड्रिंक की जगह नारियल पानी

एक मॉकटेल फ्रेश की तरह लग सकता है, लेकिन ये सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। आपको इसकी बजाए नारियल पानी पीना चाहिए।

# कीलोंग घूमने के दौरान जरूर करें ये एक्टिविटी, लाइफटाइम के लिए यादगार बन जाएगी ट्रिप

अक्सर लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। वैसे तो इस राज्य में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें मौजूद हैं, लेकिन आप चाहें तो इस बार कीलोंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बता दें कि यह राज्य की एक बेहद खूबसूरत जगह है। समुद्र तल से 10,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित कीलोंग शहर में एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है। भागा नदी के तट पर स्थित कीलोंग मठों, कई मनमोहक दृश्यों और चारों ओर से हरा भरा दिखाई देता है। यहां पर आप सिर्फ बर्फ और मठों को ही नहीं, बल्कि कई एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कीलोंग की कुछ ऐसी बेहतरीन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन्हें आपको ट्रिप के दौरान जरूर करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं।

करदंग गोम्पा जाएं

कीलोंग शहर से सिर्फ 5 किमी की दूरी पर स्थित करदंग गोम्पा लाहौल घाटी का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। यहां पर आपको प्राचीन बौद्ध धर्मग्रंथों, और म्यूरल्स का एक बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आपको असीम शांति का अनुभव होगा। इसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। मठ अपने आसपास बेहद मनमोहद दृश्य पेश करता है। जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है।

त्रिलोकनाथ मंदिर

कीलोंग के पास त्रिलोकपुर गांव में त्रिलोकनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां पर मौजूद प्राचीन मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों की आस्था का केंद्र है। बता दें कि यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और इस जगह का आध्यात्मिक माहौल लोगों को अपनी ओर बरबस खींचता है। आपको कीलोंग में घूमने के दौरान इस मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए।

ट्रैकिंग और हाइकिंग

कीलोंग में कई पॉपुलर ट्रैकिंग रूट्स का एक गेटवे मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी कीलोंग घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ट्रैकिंग का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। आप दारचा लामायुरू ट्रेक या ज़ांस्कर वैली ट्रेक पर भी ट्रेकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां पर ट्रेकिंग के दौरान आपको कई बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे।

एडवेंचर स्पोर्ट्स

अगर आप भी एडवेंचर एक्टिविटीज करने के शौकीन हैं तो आपके लिए कीलोंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहां पर आप भागा नदी में रिवर राफ्टिंग से लेकर ऊबड़–खाबड़ इलाकों में माउंटेन बाइकिंग और सुंदर स्थानों पर कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। यह एक्सपीरियंस आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। इन एक्टिविटीज में शामिल होकर आप बेहद करीब से हिमालय के रोमांच को करीब से जानेंगे।

लोकल फूड्स और कल्चर

आप यदि कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, तो उस जगह को तब तक अच्छे से नहीं जान पाते हैं। जब तक आप वहां के खान–पान और कल्चर से अच्छे से नहीं वाकिफ होते हैं। ऐसे में आपको कीलोंग की लोकल डिशेज जरूर चखनी चाहिए। आप कीलोंग में थुकपा से लेकर मोमोज़ और अन्य लोकल आइटम्स को चख सकते हैं। कीलोंग की फेमस जौ से बनी बियर जिसे चांग के नाम से जानते हैं, उसे भी जरूर टेस्ट करें। आप कीलोंग के लोकल कल्चर और लोकल फेस्टिवल्स व इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं।

# शुरुआत से लेकर अंत तक... इन 5 पड़ावों से होकर गुजरता है हर रिश्ता

पिछले कुछ दशकों में, रिश्तों को लेकर लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है। लोगों की इसी बदलती सोच ने आजकल के रिश्तों को पहले की तुलना में काफी ज्यादा जटिल बना दिया है। अगर आज के रिश्तों और इन्हें लेकर लोगों की सोच को समझने निकले तो ये एक बेवकूफी भरा काम होगा। आज के लोग तेज–तर्रार हो गए हैं। ये किसी के साथ रिश्ते में आना नहीं चाहते और आ जाए तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता है। ऊपर से बची हुई कसर पूरी करने का जिम्मा सोशल मीडिया ने उठा रखा है। तेज़–तर्रार लोगों को एक प्लेटफार्म मिला हुआ है, जहाँ वह जब चाहें जिससे चाहें टेक्स्टिंग, फ़्लर्टिंग से लेकर हुकअप तक की सेटिंग कर लेते हैं। ये एक तरह का पैटर्न है, जिसे आजकल के लोग रिश्तों में आने के लिए फॉलो करते हैं। हालाँकि, रिश्ते सिर्फ इसी पैटर्न पर नहीं चलते हैं। कुछ बुनियादी चरण होते हैं, जिनसे गुजरते हुए रिश्ते आगे बढ़ते हैं। आज हम रिश्तों के इन्हीं चरणों के बारे में आपको बताने वाले हैं–

स्टेज 1

किसी को जानने और समझने के पड़ाव को हनीमून स्टेज कहा जाता है। ये स्टेज रिश्ते का सबसे खूबसूरत पड़ाव होती है। इस दौरान लोग एक–दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। रिश्ते का ये खूबसूरत पड़ाव लगभग छह महीने तक चलता है, जो शानदार, मनोरंजक और आकर्षक होता है। इन छह महीनों में लोगों के दिल और दिमाग में होर्मोनों का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ये विस्फोट लोगों को आनंद, खुशी और ऊर्जा देने वाला होता है। एक्सपर्ट्स लोगों को इस स्टेज का आनंद लेने की सलाह देते हैं। लेकिन साथ ही वह लोगों को इस दौरान खुद पर नियंत्रण रखने की सलाह भी देते हैं।

स्टेज 2

हनीमून स्टेज, जो लगभग छह महीने तक रहता है, इसके खत्म होने के बाद मतभेद स्टेज शुरू होता है। ये पड़ाव

परेशानियों और लड़ाई–झगड़ों से भरा होता है क्योंकि इस दौरान लोगों की असमानताएं उभरनी शुरू हो जाती है। हनीमून स्टेज पर लोग खुद को बहुत अच्छा बनाकर पेश करते हैं और इस पड़ाव में उनकी असलियत सामने आने लगती है। ये पड़ाव दो से तीन साल तक चलता है। इसमें पार्टनर के लिए प्यार, आकर्षण और दिलचस्पी में कमी आने लगती है। ये पूरी तरह से आम बात है। एक्सपर्ट्स लोगों से इस पड़ाव में रिश्ते को तोड़े बिना अपने मतभेदों को सुलझाने की सलाह देते हैं।

स्टेज 3

मतभेद चरण के बाद, लोग अपने रिश्ते के सबसे बड़े पड़ाव का सामना करते हैं और इसे संघर्ष का चरण कहा जाता है। ये पड़ाव भी दो से तीन साल तक चलता है। इस चरण में लोगों में आक्रोश और हानि की भावना अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। इन भावनाओं के पीछे का कारण पिछले चरण के मतभेद, लड़ाई और झड़ते होते हैं, जिन्हें आमतौर पर लोगों द्वारा अनसुलझा छोड़ दिया जाता है। संघर्ष के चरण में, लोग अपने पार्टनर से कटा हुआ महसूस करने लगते हैं। बहुत से लोग इस दौरान बाहर की गतिविधियों या अन्य लोगों की तरफ आकर्षण भी महसूस करते हैं। बहुत से लोगों का रिश्ता इस चरण पर खत्म हो जाता है।

स्टेज 4

संघर्ष चरण के बाद मरम्मत या खत्म करने का पड़ाव आता है, जिसमें ज्यादातर लोगों की राहें अलग हो जाती है। मतभेद, लड़ाई–झगडे, आक्रोश जब रिश्ते में ज्यादा बढ़ जाता है तब समय फैसले लेने का होता है। रिश्ते में दो ही तरह के फैसले होते हैं या तो चीजें ठीक कर ली जाए या खत्म कर के अलग–अलग रास्तों पर आगे बढ़ा जाए। लड़ाई–झगड़ों और मतभेदों से लड़कर इंसान थक जाता है और वो बस चीजें खत्म करना चाहता है। लेकिन अगर रिश्ते में मरम्मत होने की थोड़ी भी गुंजाइश है तो थोड़ा प्रयास कर के देखा जा सकता है। लेकिन अगर रिश्ता बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया है तो आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

स्टेज 5

मरम्मत या खत्म करने के पड़ाव के बाद आता है प्रतिबद्धता/कमिटमेंट का चरण, जो लोगों के लिए कई मायनों में ख़ास होता है। पिछले चरण में जिन्होंने रिश्ते को तोड़ दिया वह एक नयी शुरुआत करेंगे और जिन्होंने साथ रहकर रिश्ते की मरम्मत करने का फैसला किया है वो साथ में अगला कदम बढ़ाएंगे। रिश्ते का ये चरण एक–दूसरे के लिए आपके प्यार को दर्शाता है। लाख परेशानियों के बावजूद आपने एक–दूसरे को चुना है और अब साथ रहने का समय है। इस चरण का आनंद लीजिये और अपनी रोमांटिक साझेदारी को आगे बढाएं।

# आपकी मसालेदानी में ही छिपा है ` प्रोस्टेट कैंसर का इलाज, इस बीमारी के लिए रामबाण है ये मसाला

दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले मसालों में शामिल दालचीनी और उसके सक्रिय घटक प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। एक ताजा अध्ययन में यह दावा किया गया है। हैदराबाद में स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद –राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर–एनआईएन) द्वारा किए गए अध्ययन में चूहों को खाने में दालचीनी और उसके सक्रिय घटक... सिनामाल्डिहाइड और प्रोसायनिडिन बी2.. दिए गए और शुरूआती स्तर के प्रोस्टेट कैंसर पर उनका प्रभाव निरोधात्मक रहा।

चूहों पर किया गया अध्ययन

इस अध्ययन का शीर्षक है 'प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने के खतरे का सामना कर रहे चूहों पर दालचीनी और उसके बायोएक्टिव कंपोनेंट का कीमोप्रिवेंटिव प्रभावश। यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। एनआईएन ने एक विज्ञप्ति में कहा है, इस अध्ययन का लक्ष्य कैंसर के खतरे का सामना कर रहे नर चूहों पर दालचीनी और उसके सक्रिय कंपोनेंट के कीमोप्रिवेंटिव प्रभाव का पता लगाना था।

दालचीनी खिलाने का दिखा फायदा

इस अध्ययन के तहत वयस्क चूहों में कैंसर होने से पहले उन्हें भोजन के माध्यम से दालचीनी और उसके बायोएक्टिव कंपोनेंट दिए गए। चूहों को 16 सप्ताह तक यह खिलाया गया। यह देखा गया कि दालचीनी या उसके सक्रिय कंपोनेंट का सेवन करने वाले चूहों में से 60–70 प्रतिशत में प्रोस्टेट सामान्य रहा। एंडोक्रायनोलॉजी विभाग के प्रमुख व अध्ययन का नेतृत्व करने वाली आयशा इस्माइल ने कहा–''हमने कीमोप्रिवेंटिव प्रभाव के संभावित तरीके का पता लगाने का प्रयास किया और पाया कि दालचीनी और उसके सक्रिय घटक ऑक्सिडेटिव तनाव को कम कर सकते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर कोशिकाओं के फैलने की गति कम कर सकते हैं।

क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर

प्रोस्टेट कैंसर तब शुरू होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि में कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। प्रोस्टेट कैंसर के 60प्रतिशत मामलों का निदान 65 या उससे अधिक उम्र के लोगों में होता है, लेकिन कम उम्र के पुरुष भी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। कई प्रोस्टेट कैंसर अधिक आक्रामक होते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाहर फैल सकते हैं, जो की घातक हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक, मोटापे जैसे कारकों से संबंधित लोगों में अन्य लोगों की तुलना में अधिक होता है।

प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण

–पेशाब करने मे मुश्किल या जलन होना।
–बार–बार पेशाब करने की इच्छा होना, खासकर रात में।
–मूत्र या वीर्य में खून आना।
–मूत्र करने मे दर्द होना।
–बैठने पर दर्द या बेचौनी, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है।
–हड्डी मे दर्द होना।

इन बीमारियों के लिए भी वरदान है दालचीनी

–इसमें पर्याप्त मात्रा में पॉलीफेनोल्स नाम के एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इस तरह बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

–दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा व शरीर के अंदरूनी हिस्सों में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

– कुछ अध्ययनों के अनुसार दालचीनी को बढ़ा हुआ ब्लड शुगर कम करने में काफी प्रभावी माना गया है।

– दालचीनी में मौजूद कुछ तत्व कैंसर कोशिकाओं के लिए एक विषाक्त पदार्थ के रूप में काम करते हैं।

– एक अध्ययन में पाया गया कि 120 मिलीग्राम दालचीनी रोज खाने से खतरनाक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।

– दालचीनी पाउडर में शहद मिलाकर इन्फेक्टेड स्किन पर लगाने से तुरन्त राहत मिलती है।

## संक्षिप्त

### कौन बनेगा आईपीएल का नया चेयरमैन? 18 सितंबर को मुंबई में होगा चुनाव

नई दिल्ली,एजेंसी। एजीएम के एजेंडे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्रिकेट एसोसिएशन को एजीएम की एसोसिएट सदस्यता देने का प्रस्ताव भी शामिल है। बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की जून में हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। एसोसिएट सदस्य को बीसीसीआई में मतदान का अधिकार नहीं होता। एजीएम में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। एजीएम के दौरान आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के दो निर्वाचित पदों के लिए चुनाव भी होगा। इनमें गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन का पद भी शामिल है। फिलहाल अरुण धूमल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं। बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी ए.के. ज्योति ने मंगलवार को चुनाव संबंधी नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में बीसीसीआई के पूर्ण सदस्यों से अपने प्रतिनिधियों के नाम चुनावी सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चुनाव के लिए प्रतिनिधि नामित करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। वैध रूप से नामित उम्मीदवारों की सूची 11 सितंबर को जारी की जाएगी। दोनों पदों पर चुनाव निर्विरोध होने की संभावना जताई जा रही है। एजीएम के एजेंडे में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (आईसीए) के प्रतिनिधि को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में शामिल करने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा बीसीसीआई के ओम्बड्समैन और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति भी बैठक के एजेंडे में शामिल है।

### एकल विजेताओं को मिलेंगे 52.66 करोड़ रुपये, इतिहास की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि

न्यूयॉर्क,एजेंसी। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों पर पैसों की जमकर बारिश होने वाली है। टूर्नामेंट के पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन को इस बार 55 लाख डॉलर (करीब 52.66 करोड़ रुपये) की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि मिलेगी। यह टेनिस इतिहास में किसी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन को मिलने वाली सबसे बड़ी पुरस्कार राशि होगी। यूएस टेनिस एसोसिएशन (यूएसटीए) ने गुरुवार को टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि का एलान किया। यूएस ओपन का मुख्य मुकाबला अगले सप्ताह से शुरू होगा। यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों को कुल 10.8 करोड़ डॉलर (करीब 1,034 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। यह पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी अधिक है, जबकि 2024 की तुलना में इसमें करीब 44 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले साल यूएस ओपन के पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन कार्लोस अल्कारेज और आर्यना सबालेंका को 50–50 लाख डॉलर मिले थे। 2025 में टूर्नामेंट की कुल खिलाड़ी पुरस्कार राशि 9 करोड़ डॉलर थी। यूएस ओपन में 128 खिलाड़ियों वाले सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में जगह बनाना भी इस बार बेहद फायदेमंद होगा। मुख्य ड्रॉ में पहुंचने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 1.4 लाख डॉलर (करीब 1. 34 करोड़ रुपये) मिलेंगे। पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स की विजेता टीम को 10 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी। वहीं रनर–अप टीम को 5 लाख डॉलर मिलेंगे। व्हीलचेयर सिंगल्स के चैंपियन खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। उन्हें 1.04 लाख डॉलर मिलेंगे। यूएसटीए ने खिलाड़ियों के लिए एक नए प्लेयर सपोर्ट प्रोग्राम की भी घोषणा की है। इसके तहत शुरुआत में 20 लाख डॉलर की राशि तय की गई है। यह रकम पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खिलाड़ियों को अतिरिक्त सुविधाएं और लाभ देना है। साथ ही यह मौजूदा पेंशन फंड को भी सपोर्ट करेगा। यूएसटीए के सीईओ क्रेग टिली ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए यह वित्तीय प्रतिबद्धता एक बहुवर्षीय निवेश की दिशा में महत्वपूर्ण पहला कदम है। उनका कहना है कि यूएस ओपन खिलाड़ियों के लिए आर्थिक अवसरों के लिहाज से टेनिस का सबसे महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। इसी बीच खिलाड़ियों को ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों से जुड़े फैसलों में ज्यादा भूमिका देने के लिए ग्रैंड स्लैम प्लेयर काउंसिल के गठन की भी घोषणा की गई है। यह कदम खिलाड़ियों की ओर से टूर्नामेंटों की आय और निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी की मांग के बीच उठाया गया है।

### 31प्रतिशत भारतीय पांच साल में चाहते हैं अपना आशियाना

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीयों में अपना घर खरीदने की चाह तेजी से बढ़ी है। 31 फीसदी लोग अगले पांच साल में घर खरीदना अपना सबसे बड़ा वित्तीय लक्ष्य मानते हैं। बचत और निवेश पर भी जोर बढ़ा है। क्या भारतीय अब खर्च से ज्यादा लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं? भारतीयों में वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ने के साथ अब खर्च के बजाय लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा पर जोर बढ़ रहा है। होम क्रेडिट इंडिया की द ग्रेट इंडियन वॉलेट 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, निम्न–मध्यम वर्ग के 31 फीसदी लोग अगले पांच साल में अपना घर खरीदना सबसे बड़ा वित्तीय लक्ष्य मानते हैं। पिछले साल के मुकाबले इसमें 8 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। घर खरीदना महिलाओं की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। 40 फीसदी महिलाओं ने अगले पांच साल में घर खरीदने को लक्ष्य बताया, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 29 फीसदी रहा। घर खरीदने के बाद कारोबार शुरू या बढ़ाना 25 फीसदी लोगों की प्राथमिकता रही। सर्वे में शामिल लोगों की औसत मासिक आय 35 हजार और जरूरी खर्च 21 हजार रुपये रहा। 53: लोग खर्च निकालने के बाद बचत कर पा रहें। 36: के पास कुछ बचत नहीं कर पाते। 11: लोग उधार लेकर खर्च चलाते हैं। घर के बाद कारोबार और बच्चों की पढ़ाईरू पांच साल के लोगों के वित्तीय लक्ष्यों में मकान खरीदना 31प्रतिशत, कोई कारोबार शुरू करना या उसे बढ़ाना 25प्रतिशत, बच्चों की शिक्षा 14प्रतिशत, कर्ज चुकाना 10प्रतिशत और कार खरीदना 9प्रतिशत शामिल है।

# यशस्वी–वैभव सूर्यवंशी पर बरसे संजय मांजरेकर आईसीसी–बीसीसीआई से क्यों की सख्त से सख्त सजा की मांग?

कोलंबो,एजेंसी। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मांजरेकर की यह मांग दोनों के हालिया विवादों के बाद आई है। वैभव ने हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ आउट होने के बाद एक खिलाड़ी को धक्का दिया था। वहीं, यशस्वी जायसवाल श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के कोलंबो टेस्ट में आउट होने के बाद असिथा फर्नांडो से भिड़ गए थे। इस दौरान उनका हेल्मेट असिथा के सिर से टकराया था। मांजरेकर ने कहा कि सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देने से आदत नहीं सुधरेगी और यह खिलाड़ियों को ऐसी हरकतें दोहराने के लिए प्रेरित करेगा। मांजरेकर का मानना है कि ये हरकतें कई बार हो चुकी हैं और सख्त सजा न देने पर आगे भी होंगी। उन्होंने सूर्यवंशी की लड़ाई को यशस्वी की लड़ाई से जोड़ते हुए सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ देने पर सवाल उठाए। मांजरेकर ने अपने एक्स अकाउंट पर आईसीसी और बीसीसीआई को टैग कर पोस्ट करते हुए कहा, वैभव जब भारत–ए से खेल रहे थे और अब यशस्वी, अगर आप इसी तरह से इन हरकतों को जाने देते रहेंगे तो यह घटनाएं होती रहेंगी। आप उन्हें बार–बार ऐसा करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। यह खेल के लिए अच्छा नहीं है और न ही खिलाड़ियों के भविष्य के लिए।

यशस्वी और असिथा, दोनों पर आईसीसी आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के लिए उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों को एक–एक डिमेरिट अंक भी दिया गया। आईसीसी के मुताबिक दोनों ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए बनाए गए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.12 का उल्लंघन किया, जो किसी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से जुड़ा है। यशस्वी की इस हरकत पर उन्हें दुनिया भर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि यशस्वी के लिए सबसे अच्छा यही होता

कि वह बस वहां से चले जाते। भोगले ने कहा, मैं जायसवाल से बस इतना कहना चाहता हूं कि हां, हो सकता है जो कहा गया, वह नहीं कहा जाना चाहिए था। लेकिन जैसा आप देते हैं, वैसा आपको लेना भी होगा। सबसे आसान रास्ता बस वहां से चले जाना है। इस मामले पर अजय जडेजा का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि मैदान पर मजाक और स्लेजिंग तब तक ठीक है, जब तक भाषा और व्यवहार की सीमा न लांघी जाए। जडेजा ने कहा, जब यशस्वी फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने निरोशन डिकवेला से कुछ कहा था। तब हमने कहा था कि मैदान पर मजाकिया नोकझोंक अच्छी है, जब तक आपकी भाषा में कुछ गलत न हो। अगर कोई व्यक्ति खुद पर हंस नहीं सकता, तो उसे दूसरों पर भी नहीं हंसना चाहिए। अगर आप किसी बात को खुद पर नहीं ले सकते, तो मैदान पर वह बात दूसरों से भी नहीं कहनी चाहिए। भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा था, श्मुझे लगता है कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने यशस्वी से कुछ कहा होगा और यह सब मैच की गर्मी में हुआ होगा। जाहिर तौर पर, मुझे नहीं लगता कि जायसवाल को फर्नांडो के इतने करीब जाना चाहिए था, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हो जाता है। इसी साल भारतीय–ए टीम श्रीलंका–ए और अफगानिस्तान–ए के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के लिए श्रीलंका के दौरे पर गई थी। इसी सीरीज के चौथे मुकाबले में मैच टाई हुआ और फिर सुपरओवर से फैसला आया। सुपरओवर के बाद श्रीलंका ए के खिलाड़ी विशेन हलाम्बागे और वैभव सूर्यवंशी के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों आपस में भिड़ते दिखे थे। हलाम्बागे और डिकवेला पर श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) द्वारा नियुक्त मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने अलग–अलग मामलों में कार्रवाई की थी। सजा क्या मिली थी, इसका पता नहीं चला था। इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि सूर्यवंशी और कप्तान तिलक वर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया या उन पर आधिकारिक कार्रवाई की गई थी। तिलक समेत भारतीय खिलाड़ियों की अंपायरों के साथ लंबी बहस हुई थी और वे कम रोशनी में सुपर ओवर कराने पर जोर दे रहे थे।

# कोलंबो पहुंचे सूर्यकुमार यादव: श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या से क्यों मिले ?

कोलंबो,एजेंसी। सूर्यकुमार यादव इस समय भारतीय टी20 टीम की योजनाओं से बाहर हैं, लेकिन उनकी वापसी की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। श्रीलंका में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या से उनकी मजेदार बातचीत ने भी सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा। वहीं, बीसीसीआई के एक सूत्र ने साफ किया है कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर सूर्यकुमार की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। कोलंबो में एक कार्यक्रम के दौरान सूर्यकुमार यादव की मुलाकात श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या से हुई। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई और इस दौरान सूर्या ने जयसूर्या के फिटनेस लेवल को लेकर मजाक किया। सूर्यकुमार ने श्रीलंकाई दिग्गज से पूछा कि क्या वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, शफिट हो रहे हैं, वापसी की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि 100 फीसदी वापसी की तैयारी है। सूर्यकुमार की इस बात पर जयसूर्या मुस्कुरा दिए। दोनों के बीच हुई इस छोटी सी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने इसे खूब पसंद किया। सूर्यकुमार यादव ने 2026 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी और टीम को खिताब दिलाया था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उनका दौर अचानक बदल गया। बल्लेबाजी में खराब फॉर्म के चलते उन्हें पहले टी20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया और फिर आयरलैंड तथा इंग्लैंड दौरे के लिए टीम से भी बाहर कर दिया गया। बीसीसीआई ने सूर्यकुमार की जगह श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का नया कप्तान बनाया। हालांकि, अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। भारत को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में 0–2 से हार का सामना करना पड़ा।

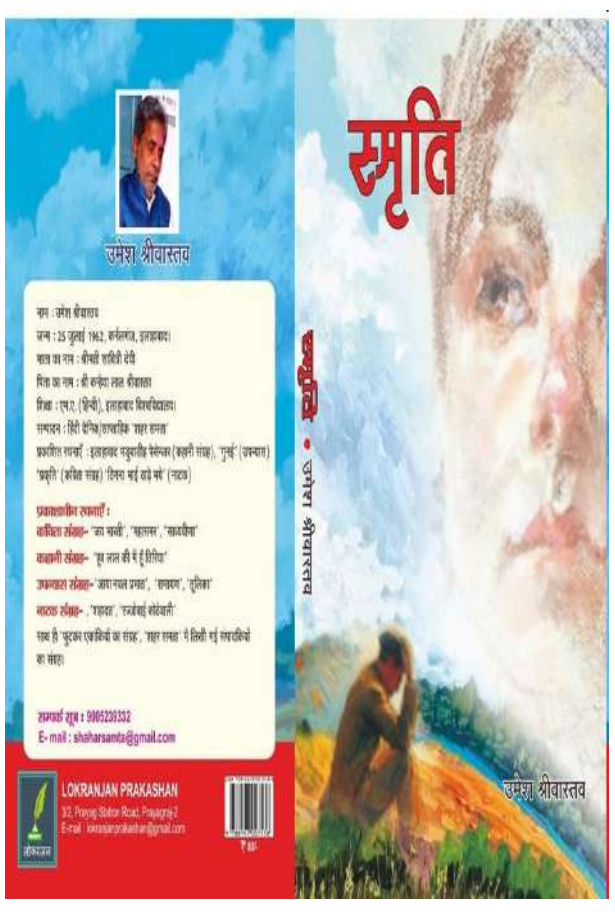


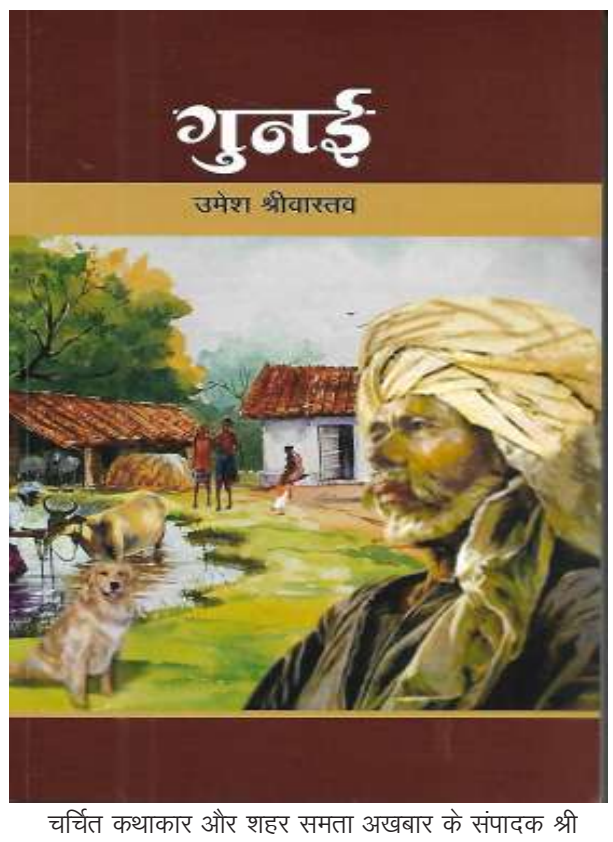


चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

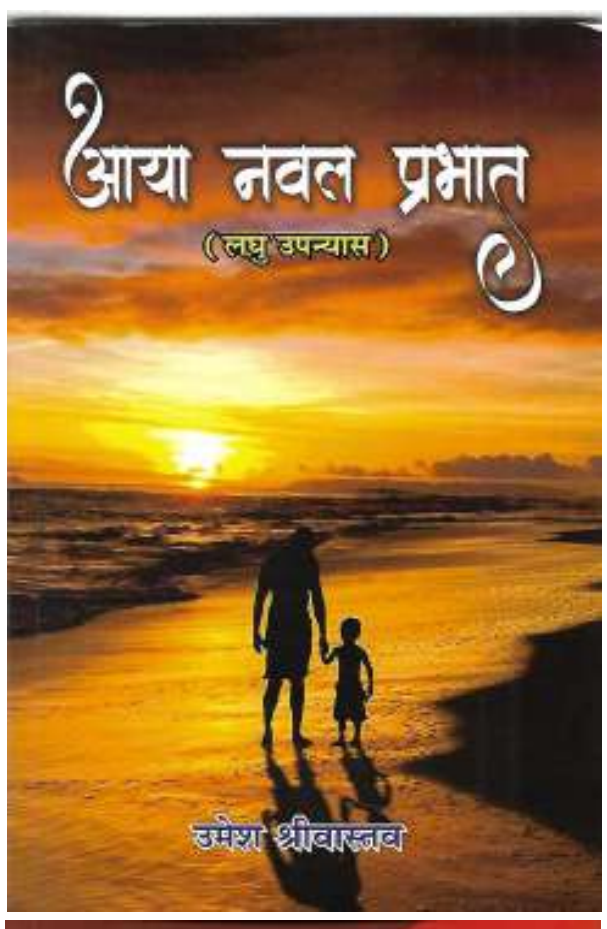


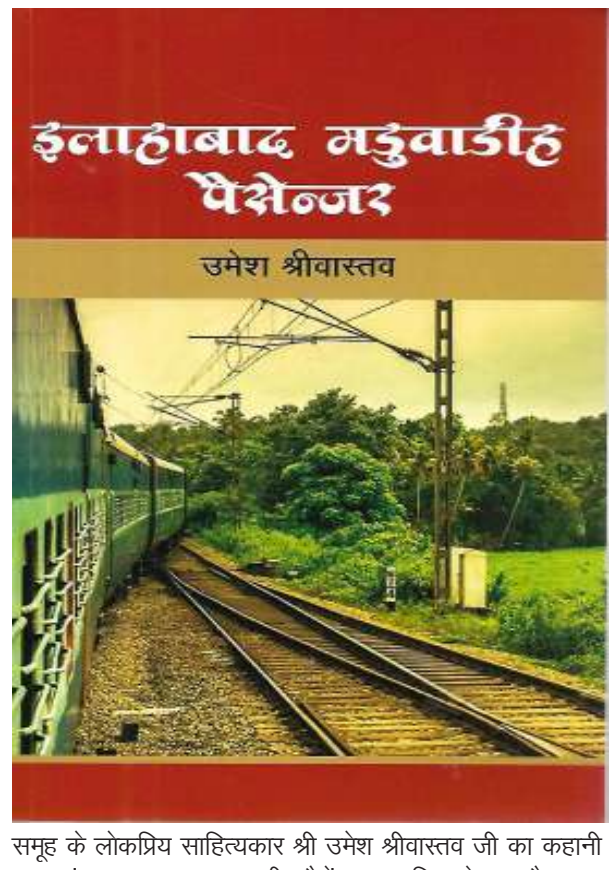


समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

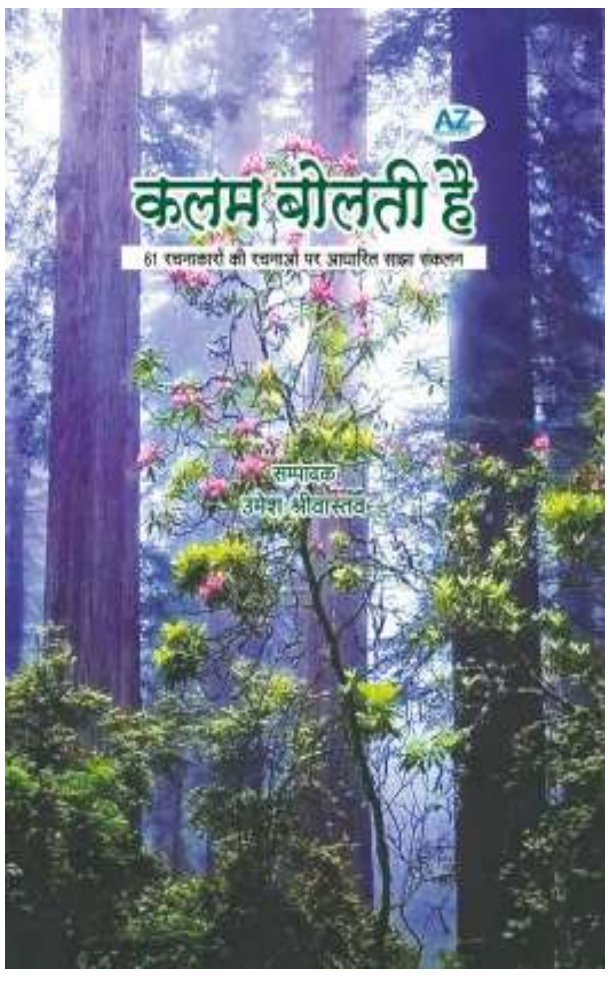


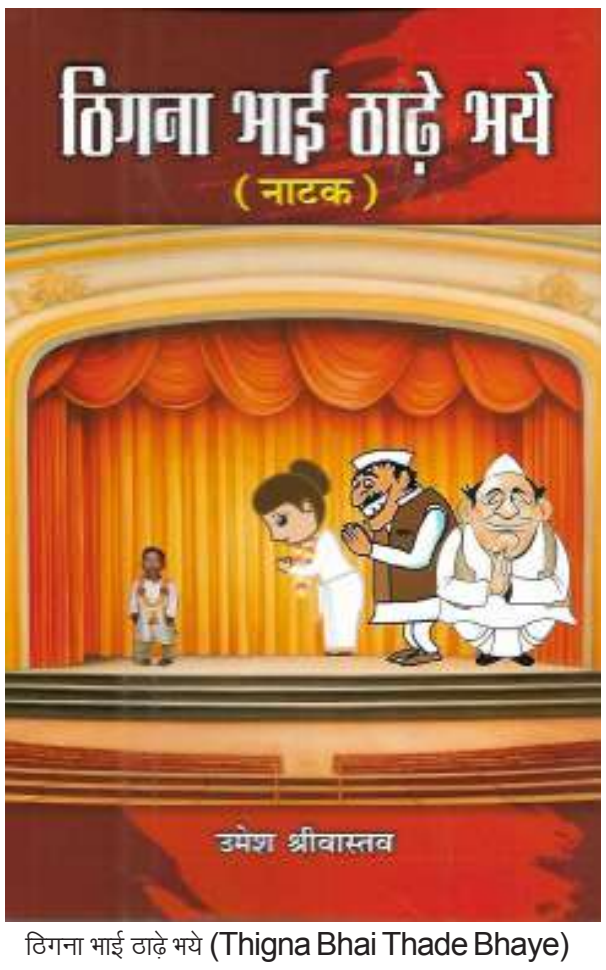


ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

## संक्षिप्त

### पाकिस्तान में बड़ा हादसा: इस्लामाबाद के शीर्ष अस्पताल पीआईएमएस में लगी आग, 15 नवजातों की मौत

एएनआई, इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बुधवार को एक सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग

वार्ड में आग लगी। इसके कारण 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। यह जानकारी श्डॉनश की रिपोर्ट के अनुसार है। यह घटना राजधानी के सबसे बड़े और अच्छी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पताल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में हुई। जियो न्यूज ने बताया कि आग लगने की घटना में 15 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि, हताहतों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीआईएमएस की प्रवक्ता ने क्या कहा? पीआईएमएस की प्रवक्ता डॉ. अनीजा जलील ने श्डॉनश अखबार को बताया कि जिस वार्ड में आग लगी, वहां 15 बच्चे थे। उन्होंने कहा, श्हो सकता है कि रात में कुछ बच्चों को छुट्टी दे दी गई हो, इसलिए अभी हताहतों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती। आग की वजह क्या है? घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी मालूम होती है। उन्होंने बताया कि आग सुबह करीब 7 बजे लगी थी। उन्होंने कहा कि आग बुझा दी गई है, लेकिन कूलिंग प्रोसेस में कुछ समय लगेगा। वहीं, रेस्क्यू अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल की नर्सरी के अंदर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने के बाद की वजह से आग लगी। इसके बाद आग तेजी से फैल गई और वार्ड में धुआं भर गया। जांच समिति गठित की गई घटना की वजह और जांच के लिए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है। प्रशासन के अनुसार, समिति आग लगने के असली कारण का पता लगाएगी और यह भी जांच करेगी कि घटना किन परिस्थितियों में हुई। इसके साथ ही कई अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई।

### न्यूयार्क में तिलक से स्वागत: मैडिसन स्क्वायर गार्डन में संबोधन, मोहन भागवत के तीन देशों के दौरे पर टिकी नजरें

एजेंसी/राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। यह उनके तीन देशों अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के ग्लोबल आउटरीच दौरे का पहला चरण है। संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत स्थानीय संगठनों के निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे के दौरान भागवत भारतीय समुदाय के लोगों के साथ–साथ स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। न्यूयॉर्क पहुंचने पर उनका पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होगा बड़ा आयोजन मोहन भागवत शनिवार को न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स' यानी 'सार्वभौमिक एकता समारोह' को संबोधित करेंगे। यह एक बड़े और विविध समुदाय की भागीदारी वाला कार्यक्रम होगा, जिसका आयोजन 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' (AHEAD) फोरम की ओर से किया जा रहा है। भागवत के इस संबोधन को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। यह आयोजन एकता, नागरिक कर्तव्य और वैश्विक सद्भाव जैसे आधुनिक विचारों के साथ हिंदू त्योहार रक्षाबंधन की पारंपरिक भावना को जोड़ते हुए मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल आयोजकों के मुताबिक, कार्यक्रम में दिन की थीम के अनुरूप विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा अलग–अलग धर्मों के प्रमुख वक्ता भी समारोह में शामिल होंगे और एकता तथा वैश्विक सद्भाव का संदेश देंगे। 25 अगस्त से शुरू हुआ तीन देशों का दौरा इससे पहले RSS के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि मोहन भागवत 25 अगस्त 2026 से अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा इन देशों में सक्रिय स्थानीय संघ इकाइयों और विभिन्न संगठनों के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, श्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 25 अगस्त 2026 से अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम का दौरा करेंगे। यह दौरा वहां के स्थानीय संघों और संगठनों के निमंत्रण पर हो रहा है। यह यात्रा RSS के चल रहे शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित की जा रही है। USCIRF की टिप्पणियों पर भारत का कड़ा पलटवार भागवत के अमेरिका पहुंचने से पहले रै को लेकर अमेरिकी संस्था 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' (न्ब्त्थ्) की हालिया टिप्पणियों पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने USCIRF को पक्षपाती संस्था बताते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि न्ब्त्थ् ने पिछले कई वर्षों में भारत के बारे में बार–बार गलत और भड़काऊ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं के बयानों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अपने एजेंडे होते हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।


### आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र
शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र
मोबाईल नम्बर 9190052 39332
919450482227


# एच–1बी वीजा में बड़े बदलाव की तैयारी: अमेरिका ने सभी वीजा अपॉइंटमेंट रोके, ऐसा क्या कर रहा ट्रंप प्रशासन ?

वॉशिंगटन, एजेंसी। एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में सभी इमिग्रेंट वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। अमेरिका के विदेश विभाग के इस कदम का मकसद वीजा नियमों को सख्त करना है ताकि उन आवेदकों की पहुंच को सीमित किया जा सके, जो अमेरिका में जरूरतमंद अमेरिकियों के लिए आरक्षित पब्लिक बेनिफिट्स (सरकारी सुविधाओं) पर निर्भर हो सकते हैं। भारतीय पेशेवरों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

एच–1बी वीजा, वही अमेरिकी वीजा श्रेणी है, जिसका उपयोग हर साल हजारों भारतीय पेशेवर अमेरिका में नौकरी करने के लिए करते हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सोमवार को शरिफॉर्मिंग द एच–वन–बी

नॉनइमिग्रेंट वीजा क्लासिफिकेशन प्रोग्रामश नामक प्रस्तावित नियम को समीक्षा के लिए व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के पास भेजा है। इस प्रस्ताव को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इससे हर साल कम से कम 10 करोड़ डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है या यह अर्थव्यवस्था, नौकरियों, उत्पादकता, प्रतिस्पध र्धा या किसी बड़े आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। समीक्षा पूरी करने की कोई समयसीमा तय नहीं फेडरल रेगुलेटरी डॉकेट के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के तहत एक प्रस्तावित नियम के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। डॉकेट में यह नहीं बताया गया है कि क्या प्रशासन योग्यता के मानकों, नियोक्ता की जरूरतों, वेतन के नियमों, सालाना चयन प्रक्रिया या अनुपालन नियमों में भी बदलाव करना चाहता है। व्हाइट हाउस की समीक्षा पूरी करने के लिए अभी कोई कानूनी समयसीमा तय नहीं की गई है। कौन सा विभाग करेगा समीक्षा

यह समीक्षा अमेरिकी सरकार के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स की ओर से की जाती है, जो व्हाइट हाउस के श्ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजटश का एक हिस्सा है। यह कार्यालय महत्वपूर्ण संघीय नियमों को प्रकाशित होने से पहले जांचता है। यह ऑफिस किसी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है, उसे एजेंसी को वापस भेज सकता है या उसमें बदलाव के साथ मंजूरी दे सकता है। नियम की जानकारी आम तौर पर समीक्षा पूरी होने और प्रस्ताव के श्फेडरल रजिस्टरश में प्रकाशित होने के बाद जारी की जाती है। नियमों का पूरा विवरण आमतौर पर समीक्षा पूरी होने और उन्हें फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किए जाने के बाद सामने आता है। इसके बाद आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाती हैं। टिप्पणियों की समीक्षा करने के बाद ही अंतिम नियम जारी करने पर फैसला होता है। ग्रेस पीरियड खत्म करने का भी सुझाव इसके अलावा यूएससीआईएस के एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है, जिसमें एच–1बी और कुछ अन्य विदेशी कर्मचारियों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड समाप्त करने का सुझाव है। अभी यह ग्रेस पीरियड कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने या अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदलने के लिए समय देता है। एच–1बी कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जो विशेष ज्ञान वाले कार्यों में काम करते हैं और जिनके पास आमतौर पर कम से कम स्नातक डिग्री या उसके बराबर योग्यता होती है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में अक्सर इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस हर साल 65,000 नए एच–1बी वीजा की सीमा तय करती है। इसके अलावा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से उच्च डिग्री प्राप्त लोगों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा उपलब्ध होते हैं।

## एक्सप्लेनर: ईरान को छलनी करने के लिए किन देशों को निशाना बनाने की तैयारी में अमेरिका, क्या भारत भी आएगा जद में

वॉशिगंटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच बीते करीब छह महीने से जारी युद्ध में अब तक ट्रंप प्रशासन को खास सफलता नहीं मिली है। पहले वित्तीय स्तर पर और उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका की ईरान को मुश्किल में डालने की हर कोशिश लगभग नाकाम हुई है। हालांकि, अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने प्रतिबंधों के जरिए ईरान को पंगु बनाने की योजना तैयार की है। बेसेंट ने इस अभियान को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट करार दिया है, जिसके तहत अमेरिका कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाने जा रहा है, जिससे न सिर्फ ईरान को, बल्कि उसके साथ किसी भी तरह से लेन–देन करने वालों को भारी नुकसान हो। बेसेंट का कहना है कि अब उनका मकसद ईरान को जिंदा रखने वाली हर लाइफलाइन को काटना है, ताकि वह इस जंग में अकेला बचे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए पूरी दुनिया के नेताओं को

फोन कर रहे हैं और ईरान से समझौतों और व्यापार पर रोक लगाने के लिए कह रहे हैं। बेसेंट ने यह नहीं बताया कि ट्रंप ने किन देशों को इसके लिए फोन किया है या अमेरिका की तरफ से किसे–कब तक निशाना बनाया जाएगा। हालांकि, उनका इशारा साफ है कि अब ईरान को घेरने के लिए उसके व्यापारिक और सामरिक सहयोगियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ईरान के सहयोगी देश कौन हैं? अमेरिका के बीते कई वर्षों से जारी प्रतिबंधों के बावजूद किन–किन देशों से ईरान का का आयात–निर्यात जारी रहा है? क्यों अमेरिका की ओर से सख्त किए जाने वाले प्रतिबंध अब भारत को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं? आइये जानते हैं... पहले जानें– क्या है अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट?

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अमेरिका का ईरान के खिलाफ चलाया गया एक व्यापक और आक्रामक प्रतिबंध अभियान है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर घोषित इस अभियान का मुख्य मकसद ईरान की सरकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों और विदेशी मुद्रा से काटना और उसके वित्तीय स्रोतों को खत्म करना है।

1. ईरान के अहम सेक्टर्स को निशाना बनाने की तैयारी

इसके तहत अमेरिका कुछ चुनिंदा देशों, संस्थाओं, शख्सियतों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा रहा है। इससे ईरान के जहाज परिवहन, सोने के आयात–निर्यात, उड्डयन सेवा, तकनीकी खरीद नेटवर्क और डिजिटल संपत्ति जैसे प्रमुख वित्तीय–लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को लक्षित करने की तैयारी की जा रही है।

2. द्वितीयक प्रतिबंधों (सेकेंडरी सैंक्शंस) का दायरा बढ़ेगा

इस ऑपरेशन के तहत द्वितीयक प्रतिबंधों के दायरे को काफी बढ़ा दिया गया है। अमेरिका ने वैश्विक साझेदार देशों को ईरान के वित्तीय बैकचौनलों को बंद करने के लिए सख्त समय सीमा दी है, ऐसा न करने पर उन्हें तत्काल द्वितीयक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रेजरी सचिव के अनुसार, देशों को ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंध पूरी तरह से काटने होंगे या फिर अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना होगा।

## कैरिबियाई सागर में अमेरिका ने एक और नाव को बनाया निशाना: चार की मौत, ट्रंप के ड्रग्स अभियान पर क्यों उठे सवाल?

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को कैरिबियाई सागर में ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही एक संदिग्ध नाव हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए। यह घटना लैटिन अमेरिका में कथित तस्करों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के महीनों से चल रहे अभियान के दौरान हुई है। अबतक कितने लोगों की मौत हुई है? इस ताजा हमले के साथ ही अमेरिकी सेना के नावों पर किए गए हमलों में मारे गए लोगों की संख्या कम

से कम 227 हो गई है। ये हमले 68 बार किए गए हैं और इनकी शुरुआत तब हुई थी जब ट्रंप प्रशासन ने लगभग एक साल पहले उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, जिन्हें वे श्नार्को–टेररिस्टश (नशीले पदार्थों के तस्कर और आतंकवादी) कहते हैं। सेना ने क्या कहा? पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरिबियाई सागर में हमलों के बारे में सेना के ज्यादातर बयानों की तरह ही,अमेरिकी सदर्न कमांड ने कहा कि उसने तस्करी के जाने–पहचाने रास्तों पर कथित ड्रग तस्करों को निशाना बनाया। सेना ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि नाव से ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक चलती हुई नाव जैसी चीज की तस्वीर दिखी, जिसके बाद एक चमक (फ्लैश) दिखाई दी। इससे पहले कब हुआ था हमला? मंगलवार को हुआ यह हमला, पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना की ओर से एक नाव पर किए गए हमले के ठीक दो दिन बाद हुआ, जिसमें ड्रग्स की तस्करी के आरोपी दो लोग मारे गए थे। यह कार्रवाई कथित तस्करों के खिलाफ अमेरिकी अभियान में दो महीने से के ज्यादा अंतराल के बाद की गई थी। ट्रंप प्रशासन कई लैटिन अमेरिकी देशों में जमीन पर भी अपना हमलावर अभियान चलाने के लिए सहयोगी देशों के साथ समझौते करने की कोशिश कर रहा है।

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस महीने पनामा की यात्रा की। इस दौरान कहा कि कोलंबिया, ग्वाटेमाला और होंडुरास इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अमेरिका उनकी जमीन पर आपराधिक समूहों के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान चला सके। ग्वाटेमाला ने ऐसे किसी समझौते पर पहुंचने से इनकार किया। इक्वाडोर ने मार्च में अमेरिका के साथ इसी तरह के मिशन शुरू किए थे।

हमले को लेकर क्या सवाल उठे?

आलोचकों ने नावों पर किए गए हमलों की कानूनी वैधता और उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि कई जानलेवा ओवरडोज के लिए जिम्मेदार फेंटानिल की तस्करी आमतौर पर मेक्सिको से जमीन के रास्ते अमेरिका में की जाती है, जहां इसे चीन और भारत से आयातित रसायनों से बनाया जाता है।

इन हमलों की कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों और सैन्य कानून के जानकारों ने कड़ी आलोचना की है। सितंबर 2025 की शुरुआत में अमेरिकी सेना की ओर से किए गए पहले हमले ने कुछ सांसदों और सैन्य कानून के अध्ययन करने वालों के बीच विशेष चिंता पैदा की थी।

## आतंकी पन्नू को फिर मिली जान से मारने की धमकी: एफबीआई और कनाडाई पुलिस ने किया सतर्क, यात्रा को लेकर कही यह बात

न्यूयॉर्क , एजेंसी। एक खालिस्तानी आतंकी ने मंगलवार को कहा कि एफबीआई और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है कि उनके जान को खतरा है। वहीं,भारत के एक व्यक्ति को 2023 में उनके खिलाफ हत्या की साजिश रचने के लिए इस साल के अंत में सजा सुनाई जाएगी। एफबीआई एजेंट ने क्या चेतावनी दी है? सिख्स फॉर जस्टिस के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि पिछले गुरुवार को उनसे मिलने आए एफबीआई एजेंटों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जब तक खतरा टल नहीं जाता, तब तक उन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए। वहीं, अगर वे यात्रा करते हैं, तो उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में एजेंसी को पहले से बताना होगा। उन्होंने बताया कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने मंगलवार को उन्हें फोन पर चेतावनी दी थी, हालांकि किसी भी कानून लागू करने वाली एजेंसी ने उस साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जिसका पता चला था। दोनों एजेंसियों से टिप्पणी के लिए भेजे गए संदेशों का तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। क्या है ड्यूटी टू वॉर्न? पन्नू, जो एक अमेरिकी और कैनेडियन नागरिक है। उसने कहा कि उन्हें अमेरिका के 'ड्यूटी टू वॉर्न'(चेतावनी देने का

कर्तव्य) कानून के तहत चेतावनी दी गई। यह कानून अमेरिकी खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश देता है कि जब उन्हें हत्या, गंभीर शारीरिक नुकसान या अपहरण के विश्वसनीय और ठोस खतरों का पता चले, ते वे संबंधित व्यक्तियों को इसकी सूचना दें। यह नई धमकी ऐसे समय में आई है जब भारत के निखिल गुप्ता, जिन्होंने फरवरी में साजिश के आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसे 2023 में पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में 20 नवंबर को सजा होनी है। निखिल गुप्ता को क्या सजा मिल सकती है? एफबीआई ने कहा है कि गुप्ता को हत्या करने का निर्देश भारत सरकार के एक कर्मचारी ने दिया था। जब गुप्ता ने कोशिश की, तो अनजाने में उसने एक अंडरकवर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर से बात की जो एक श्हिटमैनश (किराये का हत्यारा) बनकर बात कर रहा था। फेडरल सजा के नियमों के अनुसार, गुप्ता को कम से कम 20 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। पन्नू, जो एक अलग सिख देश बनाने की वकालत करते हैं। उन्होंने मंगलवार को एक फोन इंटरव्यू में कहा श्मुझे उनकी जान से मारने की धमकियों से डर नहीं लगता।श हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का प्रशासन अमेरिका और कनाडा की संप्रभुता के लिए खतरों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेगा। पन्नू ने खुद को एक सिख मानवाधिकार वकील बताया है जो पंजाब को ऐसी जगह बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं जहां सभी धर्मों को समान अधिकार हों।

## युद्ध बढ़ेगा तो भूख भीः भारत ने संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेताया- संघर्ष रोकें, वरना बढ़ेगा खाद्य संकट

एजेंसी/भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संघर्षों के कारण पैदा होने वाले मानवीय संकट को कम करने को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने की अपील की है। भारत ने चेताया कि ऊर्जा, उर्वरक, समुद्री परिवहन और कृषि व्यापार में रुकावटें वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं जिसका सबसे ज्यादा असर आयात पर निर्भर विकासशील देशों पर पड़ रहा है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन, होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर से जुड़ी परिस्थितियों को खाद्य आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर और जहाजों के सत्यापन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने मंगलवार को कहा कि आजकल के संघर्षों का असर केवल लड़ाई वाली जगहों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर–दूर तक फैलता है। ऊर्जा बाजार, उर्वरक की आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता पहुंचाने की व्यवस्था और कृषि व्यापार में रुकावटों ने दिखाया है कि क्षेत्रीय संघर्ष किस तरह दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा असर

सुरक्षा परिषद में फूड अंडर फायररू ग्लोबल और लोकल फूड संकट को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका विषय पर हुई खुली बहस में पी. हरीश ने कहा कि जो विकासशील देश खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं उन्हें इन रुकावटों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। परिषद की पहली प्राथमिकता संघर्ष से होने वाले मानवीय संकट को कम करना होना चाहिए। इसके लिए सुरक्षित, तेज और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने की सुविधा देनी होगी और संघर्ष–रोधी इंतजामों में मदद करनी होगी। प्रतिबंधों से मानवीय सहायता बाधित न हो पी. हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके उठाए गए कदम, जैसे प्रतिबंध, अनजाने में मानवीय सहायता या वैध खाद्य और कृषि व्यापार में रुकावट न डालें। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मजबूत और खाद्य–सुरक्षित समाज का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी है।


प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़



संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।